* 20th Year
* Issue: 104
* 13.08.2026 (THURSDAY)
* ROURKELA
* R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
* (Pages-6)
* Price:2.00

e-paper-www.thekalingasamachar.com

दैनिक
कलिंग समाचार
The kalingasamachar

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

एफसीआरए बिल जेपीसी को भेजा गया, विपक्ष के हंगामे के बीच कई बिल पारित

नयी दिल्ली १२/०८ (संवाददाता): विपक्ष के भारी हंगामे के बीच, लोकसभा ने बुधवार को विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026% को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके तुरंत बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच, राज्यसभा ने %राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026% पारित किया और केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026% पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया शुरू की। विपक्ष ने लगातार विरोध-प्रदर्शन जारी रखा, जबकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और सरकार हृश्वश्वज्ञ से जुड़े छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर लोकसभा में तुरंत चर्चा शुरू करने के लिए तैयार है, बशर्ते विपक्षी सांसद मर्यादा बनाए रखें और सहयोग करें। भारतीय जनता पार्टी की सांसद सुष्मिता देव ने बुधवार को कहा कि उन्होंने किसी राज्य की वेशभूषा पर कोई टिप्पणी

नहीं की और राज्यसभा से ऐसा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए जिससे भारत को सांस्कृतिक या धार्मिक आधार पर बांटने की भावना पैदा हो। यह स्पष्टीकरण उन्होंने माकपा सांसद जॉन ब्रिटास के उस आरोप के सिलसिले में दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सोमवार को सदन की कार्यवाही के दौरान भाजपा सदस्य ने उन्हें बार-बार ''लुंगीवाला'' कहा था। लोकसभा ने बुधवार को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 विपक्ष के हंगामे के बीच पारित कर दिया, जिसके तहत राज्यों को खनिज अधिकारों पर अतिरिक्त कर लगाने से रोका जाएगा।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के जरिए केंद्र सरकार ने खनिज वाले क्षेत्रों में खनिज संपदा की मात्रा से संबंधित निर्धारित मानकों के अनुसार खनिज-युक्त भूमि के विनियमन को भी अपने नियंत्रण में लेने का प्रावधान किया है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच विधेयक को सदन में चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। जनता दल (यूनाइटेड) के सांसद संजय झा ने बिहार में कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) व्यवस्था खत्म करने के लिए राज्यसभा सदस्य और पूर्व मुज्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना करते हुए बुधवार को कहा कि इस कदम से बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई और किसानों को उनकी उपज का भुगतान सीधे बैंक खातों में मिलने लगा। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान झा ने नीतीश कुमार के दो दशक से अधिक समय बाद संसद में लौटने का भी उल्लेख किया।

लोकसभा ने बुधवार को विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन (एफसीआरए) विधेयक, 2026 को विस्तृत समीक्षा और संभावित सुझावों के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (सपा) और द्रमुक ने विधेयक को अल्पसंज्यकों के खिलाफ करार देते हुए इसे वापस लेने की मांग की। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में एक भी प्रावधान अल्पसंज्यकों के खिलाफ नहीं है तथ यह सिर्फ देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ध्वनिमत से मंजूरी दी। विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि यह विधेयक गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) और अल्पसंज्यक संस्थानों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है।

असम बाढ़: सीएम सरमा ने किया एक हजार करोड़ के महापैकेज का ऐलान, पीड़ितों को हरसंभव मदद

जोरहाट १२/०८ (संवाददाता): असम सरकार ने 19 जुलाई से ऊपरी असम के शिवसागर, चराइदेव और जोरहाट ज़िलों में आई असामान्य बाढ़ के बाद राहत, सहायता और पुनर्वास कार्यों के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपये देने का वादा किया है। मुज्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि एक मोबाइल एप्लिकेशन के ज़रिए नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वे किया जा रहा है। अब तक, 960 सर्वेक्षकों ने 8,325 परिवारों का सर्वे पूरा कर लिया है और दूसरा चरण चल रहा है। उज्मीद है कि सर्वे की प्रक्रिया 15 सितंबर तक पूरी हो जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सर्वे पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से किया जाएगा और बाढ़ से प्रभावित लोग लाभार्थियों की विस्तृत सूची देख सकेंगे। जिन लोगों का नाम शुरू में छूट जाएगा, उन्हें सर्वे पूरा होने के बाद भी सूची में शामिल होने का मौका मिलेगा। मुज्यमंत्री ने उन इलाकों में %मुज्यमंत्री राहत कोष% का इस्तेमाल करके हाउसिंग कॉलोनी बनाने की

योजना का भी संकेत दिया, जहाँ बाढ़ से घर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। उन्होंने बाढ़ से हुए नुकसान के लिए इंश्योरेंस से मुआवज़ा पाने के हकदार लोगों से अपने ज़्लेम फाइल करने को कहा और बैंक लोन चुकाने में छह महीने की मोहलत या समय बढ़ाने के लिए 30 अगस्त तक आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्कूलों को फिर से चालू करने की कोशिशें चल रही हैं और सरकार का लक्ष्य 15 अगस्त तक पढ़ाई-लिखाई की गतिविधियां शुरू करना है। इस काम में मदद के लिए 793 स्कूलों में से हर एक को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है।

असम की धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार पवित्र भादा महीने के दौरान नाम प्रसंग में मदद के लिए हर %नामघर% को 1.50 लाख रुपये देने की योजना बना रही है। सरकार बाढ़ की स्थिति का फ़ायदा उठाकर पैसे कमाने या ऐतिहासिक रूप से एकजुट रहे असमिया समाज में फूट डालने वाली किसी भी नकारात्मक गतिविधि या टिप्पणी पर कड़ी नज़र रखेगी और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। मुज्यमंत्री सरमा ने बताया कि 72 यूट्यूबर ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए फ़ंड इकट्ठा किया है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अगर इस फ़ंड का इस्तेमाल सच में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए किया गया है, तो सरकार उनके प्रयासों को सज़्मान देगी; इसे किसी जांच के बजाय उनके काम को मान्यता देने की प्रक्रिया माना जाएगा।

राहुल गांधी के रूप में जिन्ना का पुनर्जन्म हुआ है-निशिकांत दुबे ने कांग्रेस नेता पर तीखा वार

नयी दिल्ली १२/०८ (संवाददाता): झारखंड में चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस सांसद पर निशाना साधते हुए, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला किया और उन्हें पाकिस्तान के संस्थापक मुहज़्मद अली जिन्ना से भी बुरा नेता बताया। बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि अगर कांग्रेस विरोध कर रहे छात्रों के साथ खड़ी है, तो उसे झारखंड सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा न करने पर ऐसा लगेगा कि पार्टी जॉर्ज सोरोस के एजेंडे पर काम कर रही है। ङ्ग पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी के रूप में जिन्ना का दूसरा जन्म हुआ है। इस टिप्पणी के

साथ, क्ष्छ्व्क सांसद ने झारखंड में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी पर अपना हमला तेज़ कर दिया और कांग्रेस नेता की तुलना जिन्ना से करने की बात दोहराई। झारखंड में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर क्ष्छ्व्क सांसद दुबे ने कहा कि वे ष्टक्चढ्ढ जांच ज़्यों नहीं चाहते? मुज़्य आरोपी धर्मेंद्र को झारखंड सरकार के एक बड़े अधिकारी के घर से पकड़ा गया था। उन्हें पता है कि अगर जांच हुई, तो उसमें हेमंत सोरेन का नाम भी आएगा। यही वजह है कि यह सब हो रहा है। उन्हें (कांग्रेस को) झारखंड सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए और यह दिखाना चाहिए कि वे छात्रों के हित में खड़े हैं। वरना, ऐसा लगेगा कि वे सोरोस के एजेंडे पर काम कर रहे हैं; जहाँ भी क्ररू के ख़िलाफ़ विरोध-प्रदर्शन होता है, वहाँ राहुल गांधी नज़र आते हैं। वे जिन्ना से भी बुरे नेता हैं।राहुल पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि अगर वो अमीर पार्टी के नेता हैं मल्लिकार्जुन खरगे तो उनको झारखंड का पिछड़ापन, गरीबी और भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता है।

उनको तो डूब मरना चाहिए। मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के डूब मरने जैसी स्थिति है कि जिस तरह से झारखंड के बच्चे सड़कों पर हैं और वहां के अधिकारी जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। इतना निरंकुश तानाशाह तो मैंने कभी देखा ही नहीं। धर्मेंद्र जो मुज़्य आरोपी है वो वहां के सबसे शीर्ष्थ पदाधिकारी के घर से पकड़ा गया। ये ष्टक्चढ्ढ जांच ज़्यों नहीं देना चाहते हैं ज़्योंकि धर्मेंद्र वहां के शीर्ष्थ अधिकारी के घर से पकड़ा गया है, उनका कंप्यूटर ऑपरेटर है।

संसदीय लोकतंत्र का अपमान! किरेन रिजिजू बोले-चर्चा से भाग रहा विपक्ष

नयी दिल्ली १२/०८ (संवाददाता): संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को कहा कि वे अपनी ज़िंदगी में पहली बार पूरी तरह से निराश महसूस कर रहे हैं। वे एक ऐसी स्थिति देख रहे हैं जहाँ सरकार संसद में चर्चा करना चाहती है, लेकिन विपक्ष उससे भाग रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति की कल्पना करना भी मुश्किल है, ज़्योंकि संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष ही चर्चा की मांग करता है और सरकार जवाब देती है। उन्होंने कहा कि मैं पूरी तरह से परेशान हूँ। अपनी ज़िंदगी में पहली बार मैं ऐसा नज़ारा देख रहा हूँ जहाँ सरकार संसद में चर्चा करना चाहती है, लेकिन विपक्ष उससे भाग रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, ज़्योंकि संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष ही चर्चा की मांग करता है और सरकार जवाब देती है।

लेकिन यहाँ, सरकार खुद कह रही है कि हम चर्चा करेंगे और जवाब देंगे, फिर भी विपक्ष सुनने को तैयार नहीं है। ज़्या आप ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकते हैं?

किरेन रिजिजू ने आगे कहा कि यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है ज़्योंकि उन्होंने बार-बार इस मामले पर चर्चा करने की इच्छा जताई है, फिर भी विपक्ष सहमत होने से इनकार कर रहा है। उन्होंने कहा कि नतीजतन, गृह मंत्री को एक और पत्र लिखना पड़ा; गृह मंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर फिर से कहा कि हम खुली, व्यापक और विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं और उनसे विपक्ष के नेताओं को इसके लिए मनाने का आग्रह किया। ज़्या आपने कभी ऐसी कोई बात सुनी है? सरकार खुद अध्यक्ष से गंभीरता से अनुरोध कर रही है कि वे विपक्ष को चर्चा में भाग लेने के लिए मनाएं। आज भी, हमने बार-बार विपक्ष से तुरंत चर्चा शुरू करने का आग्रह किया, लेकिन उनमें हिज़्मत की कमी है। यह देश के लिए अच्छा नहीं है। रिजिजू ने यह भी पूछा कि अगर चर्चा ही नहीं होगी तो संसद कैसे काम करेगी और कहा कि अगर विपक्ष सुनना ही नहीं चाहता तो सरकार संसद में अपनी बात नहीं रख सकती और न ही जवाब दे सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने प्लेकार्ड दिखाना, नारे लगाना और यहाँ तक कि अपशज़्द कहना भी आम बात बना दिया है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस सांसदों को शायद लगता है कि उनका एकमात्र काम नारे लगाना, प्लेकार्ड दिखाना और लोगों को अपशज़्द कहना है। उन्होंने यह भी कहा कि वे भूल गए हैं कि संसद बहस और चर्चा के लिए होती है। उन्होंने आगे कहा कि कल सत्र का आखिरी दिन है और हमने आज भी उनसे अपील की है। मैं बहुत भारी और दुखी मन से यह कह रहा हूँ- मैं सचमुच निराश हूँ कि विपक्ष संसद में बहस से भाग रहा है।

यह एफसीआरए बिल वापस लिया जाए! प्रियंका गांधी का सरकार पर करारा हमला

नयी दिल्ली १२/०८ (संवाददाता): कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को नई दिल्ली में %विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026% का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि उनकी पार्टी का स्पष्ट रुख है कि इस विधेयक को वापस लिया जाना चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारा रुख यह है कि इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए। उसी दिन, केंद्र सरकार के संसद में प्रस्ताव पेश करने के बाद इस बिल को औपचारिक रूप से संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया। कार्यवाही फिर से शुरू होने के बाद केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में यह प्रस्ताव पेश किया। लोकसभा की कामकाज की अतिरिक्त सूची में बताया गया कि समिति में 31 सदस्य

होंगे—21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। प्रस्ताव में कहा गया कि विदेशी योगदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को सदनों की एक संयुक्त समिति के पास भेजा जाए, जिसमें इस सदन के 21 सदस्य (जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष नामित करेंगे) और राज्यसभा के 10 सदस्य (जिन्हें राज्यसभा के सभापति नामित करेंगे) शामिल हों। समिति को बिल की गहराई से जांच करने का काम सौंपा गया है और उसे 2026 के शीतकालीन सत्र के पहले हफ़्ते के आखिरी दिन तक संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि संयुक्त समिति की बैठकों के लिए कोरम (न्यूनतम सदस्यों की संज़्या) कुल सदस्यों का एक-तिहाई होगा।विपक्ष के कुछ सदस्यों ने भी बिल को वापस लेने की मांग का समर्थन किया। कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने बिल को वापस लेने की मांग की.

छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर हर सवाल का संसद में दूंगा जवाब, लोस स्पीकर को अमित शाह का पत्र

नयी दिल्ली १२/०८ (संवाददाता): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि आप जानते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने %बिज़्नेस एडवाइज़्री कमिटी% की बैठक में सरकार की ओर से हृश्वश्वज्ञ परीक्षा को लेकर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर संसद में चर्चा कराने पर सहमति जताई है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि विपक्ष की मांग से पहले ही, संसद के मौजूदा सत्र के दौरान %पज़्लिक एग्ज़ामिनेशन्स (प्रिवेंशन ऑफ़ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026% पर चर्चा हुई थी; फिर भी, उस समय सदन में विपक्ष के किसी भी सदस्य ने हृश्वश्वज्ञ परीक्षा के बारे में कोई राय नहीं रखी थी। इसके

बावजूद, सरकार इस मुद्दे पर फिर से चर्चा करने के लिए तैयार है। शाह ने आगे कहा कि मेरा आपसे अनुरोध है कि आप विपक्ष से बातचीत करें और आपसी सहमति के आधार पर, आज से ही चर्चा के लिए उतना समय—चाहे दिनों में हो या घंटों में—तय करें जितना आप उचित समझें। मैं इस मुद्दे पर चर्चा में भाग लेने के लिए तय समय पर सदन में मौजूद रहूंगा और विपक्ष द्वारा उठाए गए सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। इससे पहले शाह ने बुधवार को विपक्ष को संसद में चर्चा के लिए 24 घंटे का समय दिया। उन्होंने कहा कि वे उनके सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं और बुधवार दोपहर 3 बजे से गुरुवार दोपहर 3 बजे तक सदन में मौजूद रहेंगे। शाह ने कहा कि सबसे पहले, %लापता%, %भाग गए% जैसी बातें भारत के सार्वजनिक और संसदीय जीवन में आजकल ज़्यादा सुनने को मिल रही हैं। जब से सत्र शुरू हुआ है, मैं नियमित रूप से संसद आ रहा हूँ; मैं अपने चैंबर में बैठता हूँ, लेकिन चूँकि विपक्ष संसद को—दोनों सदनों में से किसी में भी—काम नहीं करने दे रहा है, तो कोई ज़्या करे? अमित शाह ने आगे कहा कि जहाँ तक चर्चा की बात है, हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ कर दिया है कि सरकार हृश्वश्वज्ञ विरोध-प्रदर्शनों पर पूरी चर्चा के लिए तैयार है। हमने कहा था कि समय तय किया जाए और विपक्ष तैयार रहे। उनकी शुरुआती माँग यही थी, और हमने उसे मान लिया। मैंने भी कहा है कि मैं संसद में किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, फिर भी वे बस चर्चा नहीं होने देना चाहते। अब जनता को तय करने दें कि कौन भाग रहा है। उन्हें आज दोपहर 3ः00 बजे तक स्पीकर को एक पत्र सौंपने दें। हम आज दोपहर 3ः00 बजे से कल दोपहर 3ः00 बजे तक सभी पहलुओं पर चर्चा के लिए तैयार हैं। मैं सदन में बैठूँगा; मैं सबकी बात सुनूँगा और हर बात का जवाब दूँगा।

गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं इस बात पर भी चर्चा करूँगा कि वे चर्चा ज़्यों नहीं होने देना चाहते थे। मोदी जी के नेतृत्व में ह्लढ्ढ सरकार किसी भी चीज़ पर चर्चा करने के लिए तैयार है; उन्हें बस संसद को काम करने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष से कहना चाहता हूँ- स्पीकर को दोपहर 2ः00 बजे तक एक पत्र सौंपें, हम दोपहर 3ः00 बजे चर्चा शुरू करेंगे, और मैं कल दोपहर 3ः00 बजे तक सभी सवालों के जवाब दूँगा।

विविध समाचार

बिहार में फिर दौड़ेगी शुगर मिल की चाशनी, सुधा की तर्ज पर वेजफेड बूथ भी खुलेंगे

पटना १२/०८ (संवाददाता): सरकार के सात निश्चय-3 के तहत् समृद्ध उद्योग-सशक्त बिहार की परिकल्पना अंतर्गत राज्य में बंद चीनी मिलों को पुन: परिचालित करने के संकल्प को पूरा करने के लिए राज्य सरकार बड़े कदम उठा रही है। इसके तहत मधुबनी के सकरी में पूर्व से बंद पड़े चीनी मिल की भूमि पर नये सहकारी चीनी मिल तथा दरभंगा के रैयाम में आदर्श शुगर कॉज़्प्लेज़्स का निर्माण कराया जाना है।

इन्हें इंडिया पोटाश लिमिटेड के माध्यम से स्थापित एवं संचालित किया जाएगा। चीनी मिल के साथ वहां पर पावर जनरेशन प्लांट, डिस्टलरी और कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की भी स्थापना की जाएगी। ये बातें सहकारिता मंत्री श्री रामकृपाल यादव ने बुधवार को सूचना भवन के संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं। उन्होंने कहा कि गन्ना उत्पादक किसानों को शामिल करके सहकारी चीनी मिल समिति का गठन किया जा रहा है। एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत पोर्टल तैयार करके किसानों को आमंत्रित किया गया है। अभी तक इसके लिए 10,000 से 15,000 किसानों ने आवेदन किए हैं। सहकारिता विभाग की कोशिश ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, इसके लिए तेजी से काम किए जा रहे हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़, आधुनिक और नवाचार आधारित बनाने के लिए बिहार राज्य सहकारिता नीति, 2026 लागू की गई है। इसके जरिए विकसित बिहार के निर्माण में सहकारिता की प्रभावी एवं व्यापक भूमिका सुनिश्चित की जा रही है। इस नीति से राज्य में सहकारिता के क्षेत्र में क्रांति आएगी और इसका तेजी से विकास होगा। नई सहकारिता नीति से रोजगार के बेहतर अवसर विकसित होंगे। पारंपरिक सहकारी संस्थाओं को आधुनिक तकनीक, डिजिटल नवाचार, पारदर्शी प्रशासन और कुशल प्रबंधन प्रणाली से सशक्त किया जा रहा है। इस नीति के बाद अब गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में भी नई सहकारी समितियों के गठन एवं विस्तार को प्रोत्साहित किया जाएगा।

प्रेस वार्ता में माननीय सहकारिता मंत्री श्री रामकृपाल यादव ने कहा कि सहकारिता नीति के माध्यम से युवाओं, महिलाओं, किसानों, उद्यमियों और वंचित समुदायों को सहकारिता आंदोलन से जोड़कर आत्मनिर्भरता, उद्यमिता और सामूहिक समृद्धि को बढ़ावा दिया जाएगा। विभाग सज़्जी के कलेज़्शन सेंटर में बेहतर आधारभूत संरचना विकसित करेगा। 350 पंचायतों में सज़्जी संग्रहण केंद्र और 50 प्रखंडों में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। हर थाली में बिहार की तरकारी हो, इसके लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पर किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जल्द ही सुधा डेयरी के बूथ की तरह तरकारी बूथ %वेजफेड% के माध्यम से जगह-जगह खोले जाएंगे। इससे रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। इससे स्थानीय स्तर पर सज़्जी उत्पादन करने वाले किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को विज़ीय वर्ष 2026-27 के रबी मौसम से राज्य में लागू करने की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत किसानों को उनकी कृषि लागत के समतुल्य क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान सुनिश्चित होगा। किसानों को बहुत कम प्रीमियम राशि देनी होगी और प्रीमियम में राज्य एवं केंद्र सरकार भी अपना अंश देंगी। खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में 36.85 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के विरुद्ध 6902 समितियों के माध्यम से 5.40 लाख किसानों से 36.79 लाख मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई। अधिप्राप्त धान के विरुद्ध राज्य खाद्य निगम को 24.57 लाख मीट्रिक टन यानी 98.47 प्रतिशत चावल की आपूर्ति की जा चुकी है। राज्य की सहकारी समितियों में 7,452 गोदामों का निर्माण पूरा हो चुका है। इससे 18.827 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता का सृजन हुआ है।

अंतर्राष्ट्रीयसंबंध

%सहकारिता में सहकार% के तहत 186 दुग्ध सहकारी समितियों, 618 पैज़्स, 19 प्राथमिक सज़्जी उत्पादक सहकारी समितियों और सात अन्य सहकारी समितियों को बैंक मित्र के रूप में विकसित कर माइक्रो-एटीएम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया गया है। 16 अगस्त 2026 से एक माह तक विशेष अभियान चलाकर दुग्ध सहकारी समितियों, पैज़्स, पीवीसीएस, अन्य सहकारी समितियों और उनके सदस्यों के खाते खोले जाएँगे।

पैज़्सों में व्यावसायिक विविधीकरण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 300 प्रकार की सेवाएं उपलज़्ध कराने के उद्देश्य से लगभग 6425 पैज़्सों में कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए हैं। इनमें 5807 समितियां क्रियाशील हैं और पैज़्सों द्वारा अब तक 8.81 करोड़ रुपये से अधिक का व्यवसाय किया जा चुका है। जन औषधि केंद्र योजना के तहत चयनित 461 पैज़्सों में से 373 में केंद्र स्थापना की स्वीकृति दी गई है। इनमें 37 पैज़्सों को औषधि अनुज्ञप्ति, 36 को स्टोर कोड मिल चुका है और 36 पैज़्सों में संचालन शुरू हो गया है। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत 36 समितियों में 1000, 2000 और 2500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण कराया जा रहा है।

बिजनेसऑपरेशंस

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से 21 जिलों की 100 चयनित पंचायतों में 100 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन किया गया है। इनका उद्देश्य किसानों को बाजार से जोड़कर उनकी उपज का उचित मूल्य और कृषि इनपुट उपलज़्ध कराना है। वर्तमान में 50 एफपीओ ने व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर दी हैं।

वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सहकारिता विभाग द्वारा 9 से 17 अगस्त तक %हर घर तिरंगा, 2026% अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बाइक रैली, रंगोली, तिरंगे के साथ सेल्फी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनी आयोजित की जा रही हैं। इस प्रेस वार्ता में सहकारिता विभाग के सचिव श्री धर्मेन्द्र सिंह, निबंधक, सहयोग समितियां श्री रजनीश कुमार सिंह, अपर सचिव, श्री अभय कुमार सिंह, प्रबंध निदेशक, वेजफेड श्री मनोज कुमार सिंह सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

संसद में विपक्ष का हंगामा चर्चा से भागने की साजिश, नितिन नवीन बोले-जनता जानती है कौन दोषी

नयी दिल्ली १२/०८ (संवाददाता): बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विपक्ष पर जान-बूझकर संसद में बाधा डालने और अहम मुद्दों पर बहस रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता देख रही है कि बुधवार को कौन चर्चा से भाग रहा है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, नबिन ने लगातार हो रहे व्यवधानों को विपक्ष की अराजक मानसिकता का नतीजा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से अहम मुद्दों को उठाने की बार-बार कोशिशों के बावजूद, विपक्षी दलों ने कार्यवाही में बाधा डालना ही बेहतर समझा।

नबिन ने कहा कि संसद में विपक्ष की लगातार बाधा उनकी अराजक मानसिकता को उजागर करती है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सभी अहम मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार थी, लेकिन विपक्ष संसद को काम नहीं करने दे रहा था। उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है और अब जानती है कि असल में कौन चर्चा से भाग रहा है। नबिन की ये टिप्पणियां संसद में चल रहे राजनीतिक टकराव के बीच आईं, जिसमें सरकार और विपक्ष दोनों ही सत्रों के दौरान कामकाज में बाधा डालने और व्यवहार को लेकर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। राजनीति

इससे पहले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार विपक्ष के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में शाह ने कहा कि सरकार हर तरह की संसदीय बहस के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे बातचीत में शामिल होने के बजाय विरोध-प्रदर्शन का इस्तेमाल करके अव्यवस्था फैला रहे हैं। शाह ने विपक्ष से लोकसभा स्पीकर को चर्चा के लिए पत्र सौंपने को कहा और बताया कि सरकार बुधवार दोपहर 3 बजे से गुरुवार दोपहर 3 बजे तक इस मामले पर चर्चा करने के लिए तैयार है।

यह घटनाक्रम संसद में बार-बार हुए हंगामे के बाद हुआ है, जिसके कारण अज़्सर सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी और विधायी कामकाज कम हो गया। सरकार ने विपक्षी दलों से संसदीय प्रक्रियाओं के ज़रिए अपनी चिंताएँ उठाने का आग्रह किया है, जबकि विपक्ष के सदस्यों ने हंगामे और विरोध-प्रदर्शनों का बचाव करते हुए कहा है कि जिन मुद्दों को वे महत्वपूर्ण मानते हैं, उन पर चर्चा के लिए ये ज़रूरी हैं।

सम्राट चौधरी ने भारत छोड़ो आंदोलन के शहीदों को दी श्रद्धांजलि, करोड़ों पेंशनर्स को बड़ी सौगात

१२/०८ (संवाददाता): बिहार के उपमुज़्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 11 अगस्त को उन सात युवा स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी, जो 1942 में %भारत छोड़ो आंदोलन% के दौरान पटना सचिवालय पर भारतीय तिरंगा फहराने की कोशिश करते हुए ब्रिटिश पुलिस की गोली का शिकार हुए थे। बिहार के आज़ादी के संघर्ष के इतिहास में एक अहम दिन पर, चौधरी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने और उनके बलिदान को याद करने के लिए पटना के शहीद स्मारक परिसर का दौरा किया। उन्होंने याद किया कि कैसे ब्रिटिश पुलिस ने पटना सचिवालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की कोशिश कर रहे छात्रों के एक समूह पर गोलीबारी की थी, जिसमें सात युवा मारे गए थे। शहीद होने वालों में उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपद चौधरी, राजेंद्र सिंह और रामगोविंद सिंह शामिल थे। यह घटना, अगस्त 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत से अंग्रेज़ों के जाने की मांग को लेकर शुरू किए गए %भारत छोड़ो आंदोलन% का हिस्सा थी और बिहार की सबसे अहम घटनाओं में से एक मानी जाती है। 11 अगस्त को बिहार उन सात छात्रों के बलिदान को याद करता है जिन्होंने देश की आज़ादी और राष्ट्रीय पहचान के लिए अपनी जान दे दी थी। मुज़्यमंत्री चौधरी ने %बिहार पेंशन दिवस% पर राज्य भर के लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ देने के बाद उन्हें श्रद्धांजलि दी।

उप-मुज़्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि डायरेज़्ट बेनिफिट ट्रांसफर के ज़रिए 1 करोड़ 1 लाख 33 हज़ार सामाजिक सुरक्षा पेंशनभोगियों के बैंक खातों में ?1,157 करोड़ और ?72 लाख की राशि ट्रांसफर की गई। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुज़्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन को ?400 से बढ़ाकर ?1,100 कर दिया गया है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पेंशन की राशि हर महीने की 10 तारीख तक लाभार्थियों तक पहुँच जाए। चौधरी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी पात्र बुजुर्ग व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, विधवा या वंचित नागरिक सामाजिक सुरक्षा लाभों से वंचित न रहे। कैलेज़्युलेटरऔर संदर्भ डिवाइस

डायरेज़्ट ट्रांसफर सिस्टम का मकसद कल्याणकारी सहायता समय पर पहुंचाना और बिचौलियों पर निर्भरता कम करना है। इन दो घटनाओं भारत छोड़ो आंदोलन के शहीदों को सज़्मान देना और एक करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों को पेंशन ट्रांसफर करना ने बिहार में 10 और 11 अगस्त को ऐसे दिनों के तौर पर चिह्नित किया, जिनमें राज्य के आज़ादी के संघर्ष की याद और सरकार की सामाजिक कल्याण की प्रतिबद्धता, दोनों शामिल थीं।

जंतर मंतर सीजन २ का आगाज, सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए फिर होगा प्रोटेस्ट-दिपके

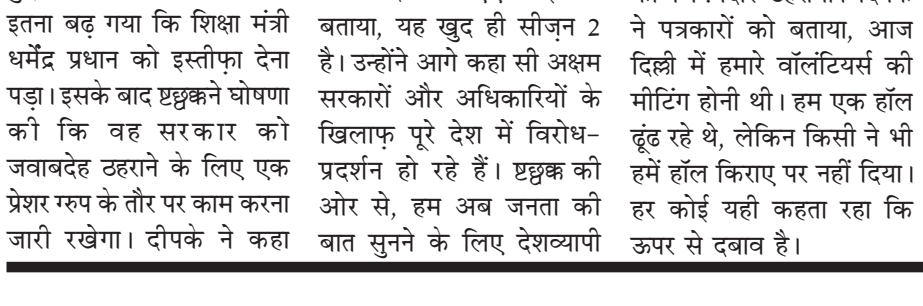

नयी दिल्ली १२/०८ (संवाददाता): कॉकरोच जनता पार्टी (ष्टछ्वक्क) एक बार फिर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है। ष्टछ्वक्कके संस्थापक अभिजीत दिपके ने बुधवार को कहा कि जंतर-मंतर का सीज़न 2 जल्द ही शुरू होगा। सीज़न 1 का ज़िक्र पिछले महीने दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के बड़े आंदोलन की ओर इशारा करता है। परीक्षा के पेपर लीक होने, छात्रों की आत्महत्या और शिक्षा में सुधार की मांगों को लेकर हुए विरोध-प्रदर्शनों का दबाव इतना बढ़ गया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ा। इसके बाद ष्टछ्वक्कने घोषणा की कि वह सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करना जारी रखेगा। दीपके ने कहा कि बहुत से लोग इंस्टाग्राम पर पूछ रहे थे कि %जंतर-मंतर% का सीज़न 2 कब शुरू होगा। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि %जंतर-मंतर% का सीज़न 2 बहुत जल्द शुरू होने वाला है। ष्टछ्वक्क के मुज़्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि दिपके की जंतर-मंतर सीज़न 2 वाली टिप्पणी दिल्ली में किसी और विरोध-प्रदर्शन तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह पूरे देश में पार्टी के लामबंदी के एक बड़े चरण की ओर इशारा करती थी। सौरव दास ने एएनआई को बताया, यह खुद ही सीज़न 2 है। उन्होंने आगे कहा सी अक्षम सरकारों और अधिकारियों के खिलाफ़ पूरे देश में विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। ष्टछ्वक्क की ओर से, हम अब जनता की बात सुनने के लिए देशव्यापी %लिसनिंग टूर% शुरू कर रहे हैं। हम एक अभियान चलाएंगे और स्वतंत्रता दिवस से शिक्षा के मुद्दे को प्राथमिकता देंगे। राजनीति

दिपके ने बुधवार को आरोप लगाया कि पार्टी को दिल्ली में अपने वॉलंटियर्स की बैठक के लिए जगह ढूंढने में मुश्किल हुई। उन्होंने दावा किया कि कई हॉल मालिकों ने ऊपर से दबाव के कारण जगह किराए पर देने से इनकार कर दिया और इसके लिए बीजेपी को जिज़्मेदार ठहराया। दिपके ने पत्रकारों को बताया, आज दिल्ली में हमारे वॉलंटियर्स की मीटिंग होनी थी। हम एक हॉल ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी ने भी हमें हॉल किराए पर नहीं दिया। हर कोई यही कहता रहा कि ऊपर से दबाव है।

कंगना रनौत ने नसीरुद्दीन शाह को कहा लोमड़ी, बोलीं- खाते देश का हैं, लड़ते पड़ोसी के लिए है

नयी दिल्ली १२/०८ (संवाददाता): दिल्ली में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ की चुप्पी पर नसीरुद्दीन शाह की टिप्पणी से शुरू हुई बयानबाज़ी के बीच, एज़्टर और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने अनुभवी एज़्टर पीयूष मिश्रा द्वारा नसीरुद्दीन शाह की आलोचना का समर्थन किया है। रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर मिश्रा के हालिया बयानों वाली एक समाचार रिपोर्ट साझा की और सीधे नसीरुद्दीन शाह को संबोधित किया। शाह द्वारा कुछ मशहूर हस्तियों की तुलना मुंह में हड्डी वाला कुज़ा जो भौंक नहीं सकता से की गई तुलना का जिक्र करते हुए, रानौत ने लिखा कि सच तो ये है हर कोई किसी ना किसी का कुज़ा है, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि मैं जिस घर (देश) की रोटी खाती हूं उसकी रखवाली करती हूं/उसके लिए लड़की हूं। नासिर साहब खाते तो इस देश का हैं लेकिन लड़ते पड़ोसी देश के लिए हैं।

उन्होंने आगे कुज़े से तुलना का बचाव करते हुए कहा कि आज के समय में इंसानों को कुज़ा कहलाना एक तारीफ है ज़्योंकि वफादारी और ज़्यूटनेस बहुत दुर्लभ है। मैं नसीरुद्दीन की तरह लोमडी के बजाय एक कुज़ा बनना पसंद करूंगी। ये टिप्पणियाँ झारखंड लोक सेवा आयोग (छ्वक्कस्ष्ट) के पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान शाह की आलोचना करने वाले मिश्रा के बयानों के बाद आई हैं। मिश्रा ने छात्रों के प्रदर्शनों पर बॉलीवुड की चुप्पी के बारे में शाह की पिछली बातों को चुनौती दी और झारखंड में छात्रों के जारी विरोध-प्रदर्शनों की ओर ध्यान दिलाया।

11 अगस्त को, कंगना रनौत ने संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ सीधे तौर पर विरोध जताया और राहुल गांधी जवाब दो लिखा हुआ बैनर दिखाया। उन्होंने झारखंड में भर्ती परीक्षाओं (छ्वक्कस्ष्ट/छ्वस्स्ष्ट) में गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के मामले में गांधी से जवाबदेही की मांग की; झारखंड में कांग्रेस पार्टी की सहयोगी सरकार है।

धर्मेन्द्र प्रधान का राहुल गांधी पर वार, झूठ फैलाकर घड़ियाली आंसू बहाने का आरोप

नयी दिल्ली १२/०८ (संवाददाता): धर्मेंद्र प्रधान ने झारखंड में हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर संसद से बचने और छात्रों के हितों के बारे में झूठे दावे फैलाने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी के पास तथ्यों की कमी है और विपक्ष के नेता, जो झूठ बोलने के आदी हैं, न तो संसद आना चाहते हैं और न ही जवाब सुनना चाहते हैं। वे बस अपना झूठ फैलाना और मगरमच्छ के आँसू बहाना चाहते हैं।झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के ख़िलाफ़ पुलिस द्वारा कथित तौर पर बल प्रयोग को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते तनाव के दौरान ये बातें कहीं गईं। प्रधान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बेबुनियाद, तथ्यहीन और झूठे आरोप लगाने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष कामकाज में बाधा डाल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी पर बिना किसी आधार या तथ्य के झूठे आरोप लगाना राहुल गांधी और कांग्रेस की राजनीतिक हताशा को दिखाता है। प्रधान ने विपक्ष पर देश और युवाओं के भले से ज़्यादा राजनीतिक हितों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार संसद में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस लोकतंत्र के मंदिर %संसद भवन% के कामकाज में बाधा डाल रही है और देश व युवाओं के हितों को नुकसान पहुंचा रही है।

प्रधान ने यह भी आरोप लगाया कि जब भी संसद के अंदर चर्चा का मौका आता है, विपक्ष बाहर विरोध-प्रदर्शन करता है, जिससे पता चलता है कि वे जवाब सुनने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने युवाओं से जुड़ी घटनाओं पर कांग्रेस के चुनिंदा रवैये का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस का लोकतंत्र भी %चुनिंदा% है ङ्क जहां उनकी सरकार है वहां युवाओं के ख़िलाफ़ हिंसा, और जहां वे राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं वहां झूठ और हंगामा।

विविध समाचार

झूले से नहीं लगता है डर, तो एक बार दुनिया के सबसे ऊंचे झूले का लें मजा

क्या आपको झूले पर बैठना पसंद है? क्या आप ऊंचे-ऊंचे झूलों पर बिना डरे झूल सकते हैं? अगर हां, तो दुनिया की सबसे ऊंचे झूले पर एक बार जरूर झूलें। इस झूले पर झूलने से आपकी सांसे और दिल की धड़कनें थम जाएंगी। लेकिन क्या आप जानते है कि अगर आपने अबतक इस झूले पर नहीं झूला है, तो अब आपको दोबारा झूलने का मौका नहीं मिल सकता है। आप में से कई लोग सोच में पड़ गए होंगे आखिर ऐसा क्यों? लेकिन आपको बता दें कि दुबई का सबसे ऊंचा झूला, जिसे आम लोगों के लिए खोला गया था उसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। दुबई के इस सबसे ऊंचे झूले को 'दुबई आई' के नाम से जाना जाता है। इसे दुनियाभर के पर्यटकों को लुभाने के लिए काफी ऐतिहासिक तरीके से डिजाइन किया गया था, लेकिन अब किसी रहस्यमी कारणों से इसे बंद कर दिया गया है।

कब हुई थी इस झूले की शुरुआत?

दुनिया का सबसे ऊंचा झूले को रहस्यमय तरीके से बंद कर दिया गया है। बता दें कि इस पर्यटक स्थल का उद्घाटन सन् 2021 में किया गया था। यहा के लोगों से इसके बंद होने के पीछे के सटीक कारणों का पता लगाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसका सही जवाब देने में सफल नहीं हो सका है।

इस झूले को बनाने में लगे 6 साल

दुनिया के इस सबसे बड़े झूले के चारों और बेहद की आकर्षक रेस्त्रा, कैफे, दुकानें और ढेर सारे कर्मचारियों का जमावाड़ा था। इसे बनाने में करीब 6 साल लगे। वहां के आसपास के कर्मचारियों का कहना है कि इस झूले को जब बनाया गया था, तो कहा गया था कि ये सदियों तक चलेगा। लेकिन अचानक से ऐसे बंद होने पर सभी परेशान हैं।

टिकट बूथ पर नहीं आते हैं लोग

बताया जा रहा है कि ये झूला लोगों के लिए लंबे समय तक आकर्षक केंद्र बनकर नहीं रहा। यहां की टिकट बूथ बिल्कुल भी खाली रहता था। झूले के आसपास रहने वाले लोग काफी ज्यादा परेशान हैं।

250 फीट ऊंचा है झूला

बता दें कि इस झूले की ऊंचाई लगभग 250 फीट है, जिसमें करीब 48 पॉड्स है। इस झूले में एक साथ 1900 बैठकर आराम से झूल सकते हैं। इस झूले को चार पाए वाले स्ट्रेक्चर से तैयार किया गया है। बताया गया है कि एक बोइंड 7,7 जंबो जेट के वजन के बराबर है। झूले का कुल वजन 900 टन है। अगर आप दुबई का ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो एक बार इस झूले के आसपास जरूर जाएं।

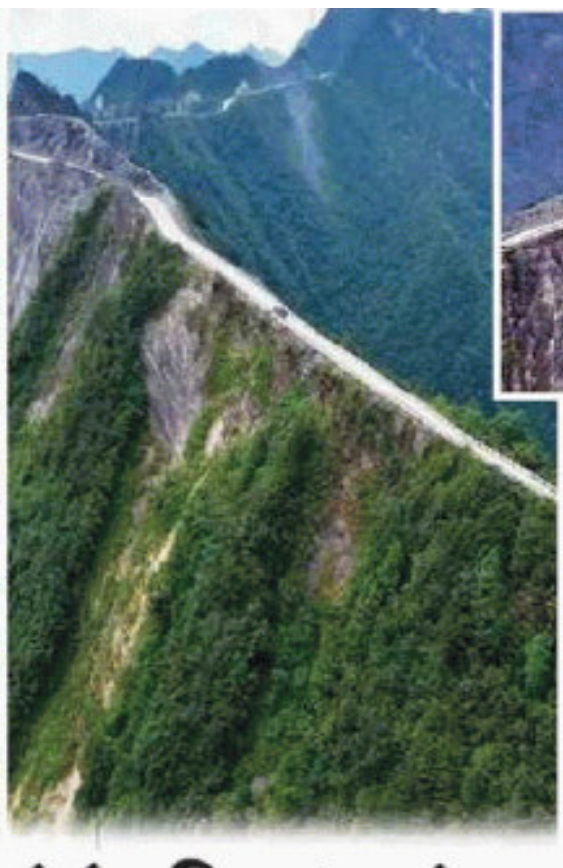

चीन अपनी इंजीनियरिंग उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध है जो लगातार दुनिया को आश्चर्यचकित करती रहती है, चाहे वह रातोंरात अस्पतालों का निर्माण करना हो या खतरनाक पहाड़ी रास्तों पर सड़कें बनाना हो। कई बार, ऐसे असाधारण कारनामे केवल चीन में ही संभव प्रतीत होते है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण चोंगकिंग प्रांत के शिझू में देखा जा सकता है। 'दाओबेड़लियांग' स्काई रोड चीनी इंजीनियरों के कौशल और सटीकता का जीता-जागता प्रमाण है।

चीन की दाओबेड़लियांग रोड

चाकू की धार पर गाड़ी चलाना: दोनों ओर 600 मीटर गहरी चट्टानें, बीच में संकरी

कुछ सड़कें साहस की परीक्षा लेती है, लेकिन चोंगकिंग की दाओबेड़लियांग रोड तो मानो किस्मत को चुनौती देने जैसी है। यह एक खतरनाक और खतरनाक रास्ता है जिसके दोनों ओर सैकड़ों मीटर गहरी खाइयाँ है। दोनों तरफ कोई सुरक्षात्मक दीवार नहीं है, जिससे गाड़ी चलाते समय ऐसा महसूस होता है मानो आप हवा में लटके एक विशाल ब्लेड पर यात्रा कर रहे हों। चीन अपनी इंजीनियरिंग उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध है जो लगातार दुनिया को आश्चर्यचकित करती रहती है, चाहे वह रातोंरात अस्पतालों का निर्माण करना हो या खतरनाक पहाड़ी रास्तों पर सड़कें बनाना हो। कई बार, ऐसे असाधारण कारनामे केवल चीन में ही संभव प्रतीत होते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण चोंगकिंग प्रांत के शिझू में देखा जा सकता है। 'दाओबेड़लियांग' स्काई रोड चीनी इंजीनियरों के कौशल और सटीकता का जीता-जागता प्रमाण है। 'दाओबेड़लियांग' नाम का अर्थ है 'चाकू की धार', जो इस सड़क के शानदार परिवेश का सटीक वर्णन करता है।

तलवार की धार पर निर्मित

यह सड़क एक बेहद संकरी पहाड़ी चोटी से होकर गुजरती है, जिसके दोनों ओर लगभग 600 मीटर गहरी खड़ी चट्टानें हैं। ऐसी परिस्थितियों में, जरा सी भी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। हालांकि पहाड़ी सड़कें तीखे मोड़ों और सीमित दृश्यता के कारण पहले से ही चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन दाओबेड़लियांग स्काई रोड को व्यापक रूप से उन सभी में सबसे खतरनाक सड़कों में से एक माना जाता है।

एक बेहद विशाल सड़क

लगभग 3 किलोमीटर लंबी इस सड़क की औसत चौड़ाई मात्र 5.5 मीटर है। कुछ जगहों पर यह 3 मीटर से भी कम चौड़ी हो जाती है, जिससे एक समय में केवल एक ही वाहन गुजर सकता है। इसके दोनों ओर कोई सुरक्षात्मक दीवार नहीं है, जिससे ऐसा लगता है मानो आप हवा में लटके एक विशाल ब्लेड पर यात्रा कर रहे हो। दिलचस्प बात यह है कि यह सड़क पर्यटकों के लिए नहीं बनाई गई थी। इसे एक पवन ऊर्जा कंपनी ने बनवाया था जिसे पवन टर्बाइन लगाने और उनकी मरम्मत करने के लिए कियाओ पर्वत की चोटी तक पहुंच की आवश्यकता थी। इसका मूल उद्देश्य रोमांच पैदा करना नहीं, बल्कि उपयोगिता प्रदान करना था।

रोमांच के शौकीनों के लिए एक वैश्विक आकर्षण

इसके बावजूद, सड़क की अनूठी बनावट और दिल दहला देने वाले खतरों ने इसे दुनिया भर के साहसिक प्रेमियों और ड्राइवरों के लिए आकर्षण का केंद्र बना दिया है। सड़क को दर्शाने वाले दर्जनों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं, और उन्हें देखना ही रोमांच पैदा करने के लिए काफी है। हालांकि इसे रूस की केबिर्ट रोड जितना खतरनाक नहीं माना जाता, लेकिन दाओबेड़लियांग स्काई रोड का रोमांच और उत्साह अनुभवी ड्राइवरों को भी डरा सकता है। केवल वही लोग इस यात्रा को करने का साहस करते हैं जिन्हें अपनी ड्राइविंग क्षमताओं पर पूरा भरोसा हो या जिन्हें ऊंचाई से डर न लगता हो। ऊपर से नजारे बेहद खूबसूरत हैं। लेकिन सड़क पर सफर करना बेहद रोमांचक है। दाओबेड़लियांग स्काई रोड चीन की सबसे उल्लेखनीय अवसंरचनाओं में से एक है, जो मानवीय साहस और आधुनिक इंजीनियरिंग के असाधारण संगम का प्रतीक है।

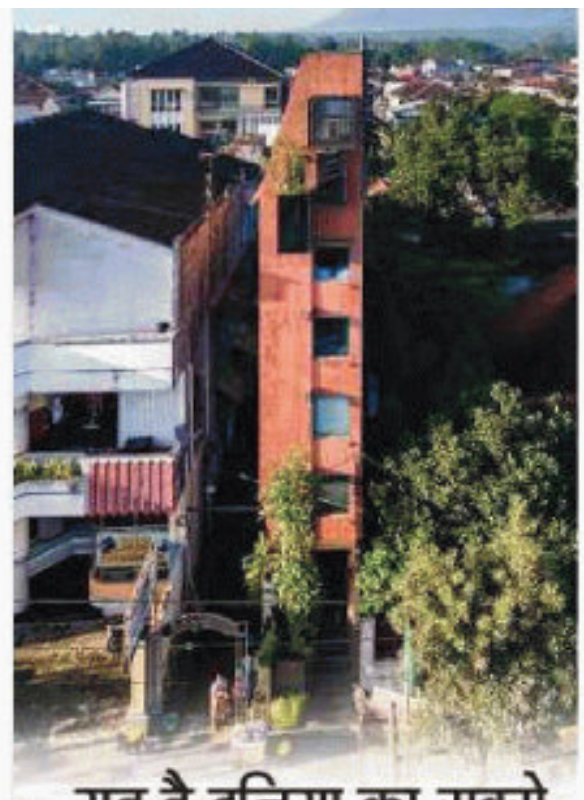

यह है दुनिया का सबसे पतला होटल, 9 फीट चौड़ी जगह में बनकर हुआ तैयार

अभी तक आपने होटल को बहुत ही बड़ा और लग्ज़रियस देखा होगा, लेकिन इंडोनेशिया के सेंट्रल जावा में सलाटिगा सिटी स्थित एक होटल पिटुरूम्स देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये लग्जरियस तो है लेकिन दुनिया का सबसे पतला होटल है। इतना पतला कि यह केवल 9 फीट चौड़ी जगह पर बना है। पांच मंजिल का ये होटल बेकर पड़ी जमीन के टूकड़े पर बनाया गया है जिसका इस्तेमाल लोग पहले डंपिंग ग्राउंड के रूप में कर रहे थे। इस होटल में सात कमरे हैं और इसे दिसंबर 2022 में खोला गया था। हर रूम में डबल बेड, शॉवर और टॉयलेट है। होटल रूम्स के अलावा रूफ टॉप रेस्टोरेंट भी है जहां इवेंट्स और आर्ट एग्जिबिशन होती है।

वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा सके बर्फीले इलाके के बीच बने इस रहस्यमयी रेगिस्तान की गुत्थी

कारक्रॉस नाम का एक छोटा सा रेगिस्तान है जिसकी गुत्थी वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा सके है. यह रेगिस्तान कनाडा के युकोन सूबे में है. जो केवल 1 मील एरिया को घेरता है. बताया जाता है कि इस रेगिस्तान के पास एक कारक्रॉस गांव है जहां केवल 301 लोग रहते है. वहां के एक स्थानीय निवासी ने बताया कि इस जगह को आज तक यहां रहने वाले लोग नहीं समझ सके हैं. उनका कहना है कि क्रॉस रिवर के किनारे कई तरह के दुर्लभ वनस्पतियां है जिनके बारे में आज भी बेहद ही कम लोग जानते है. माना जाता है कि सदियों तक किसी को इस इलाके के बारे में लोगों को पता नहीं था. कुदरती तौर पर करीब 4500 साल पहले बैनेट और नारेस झीलें आपस में मिल गई थी, जिसके चलते वहां एक पुल बन गया था. पुल का इस्तेमाल कर लोगों ने पलायन शुरू किया था. जिसके बाद धीरे धीरे यहां कारक्रॉस गांव बसा.

प्राकृतिक तौर पर पुल बनने के बाद कारिबू नाम की जंगली जनजाति का झुंड यहां आकर रहने लगा. साथ ही नताशाहीन नदी के पास शिकार के मकसद से तिलिंगित और तागिश नाम के घुमंतू कबीले रहने लगे. जिसके बाद कारिबू और क्रॉसिंग शब्दों की टोन को मिलाकर इसका नाम कारक्रॉस रखा गया. बताया जाता है कि कारक्रॉस पर जो भी आया है उसने सफेद रंग से सजे पुराने चर्च, जंग लगी कुल्हाड़ियां और सफेद रंग से सजे पुराने चर्च जरूर देखे होंगे. ये सभी चीजें क्लॉनडिक दौर की मानी जाती है. ये वो दौर है जब डॉसन सिटी और अटलिन के पास लोग सोने की खुदाई के लिये आया करते थे. अब इस वक्त की बात करें तो कारक्रॉस डेजर्ट अब एडवेंचर प्लेग्राउंड में बदल गया है. हर हफ्ते यहां लोग एडवेंचर के लिए आते है. सर्दियों के समय लोग यहां बर्फ का मजा लूटने आते है तो वहीं गर्मियों में बाइक प्रेमियों की संख्या देखने को मिलती है. माना जाता है कि कनाडा के वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों के लिए ये एक रिसर्च सेंटर है. ये वैज्ञानिक ये पता लगाने में जुटे है कि बर्फीले इलाके में ये एक छोटा सा रेगिस्तान कैसे बना हुआ है. युकोन डियोलॉजिकल सर्वे की भूवैज्ञानिक पनाया लिपॉस्की का कहना है कि कारक्रॉस कुदरत के जरिए बना है. कुदरत की 10 हजार साल की मेहनत का नतीजा माना जा सकता है. 11 से 24 हजार साल पहले विस्कॉन्सिन मैक्कोनेल ग्लेशियर बनने के दौरान ही उत्तरी युकोन में ग्लेशियर जम गया था. उस वक्त कारक्रॉस में एक किलोमीटर की बर्फ जम गई थी. बर्फ के पिघलने पर यहां बड़ी नहर बन गई थी. जिसके बाद ग्लेशियर पिघला और उत्तर-पश्चिम से रेतीली हवाएं चलने लगी जिस कारण ये एक असंभव रेगिस्तान बन गया.

वहीं कुछ अन्य लोगों का मानना है कि झील सूखने की वजह से ये रेगिस्तान बना जबकि ऐसा नहीं है. कहा जाता है कि हिम-युग, पानी और हवा ने मिलकर इस ऊंचाई पर ये अद्भुत रेगिस्तान बना दिया. कारक्रॉस को लेकर एक बात है कि ये जगह आश्चर्य और भय बनाती है. यहां जितना आगे जाना होगा उनका खौफ बढ़ता जाएगा. यहां के पर्यावरण की जटिलता को समझना बेहद ही मुश्किल है लेकिन ये जगह बेहद ही अद्भुत है.

चंदन नहीं ये है दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी, एक पेड़ ही आपको बना देगा लखपति

दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी की जब भी बात होती है तो अक्सर लोग चंदन की लकड़ी का नाम लेते है। लेकिन ऐसा नहीं। चंदन दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी नहीं है। दुनियाभर में सबसे महंगी मिलने वाली लकड़ी है अफ्रीकन ब्लैक वुड। जी हां, यह लकड़ी चंदन से कई गुणा महंगी है। साथ ही बहुत भी दुर्लभ है। अफ्रीकन ब्लैक वुड इतनी महंगी है कि इसकी एक किलो की कीमत में आप एक लग्जरी कार खरीद सकते हैं। तो चलिए जानते है, क्या है ये लकड़ी और क्यों है ये इतनी महंगी। अफ्रीकन ब्लैक वुड एक दुर्लभ लकड़ी है, इसलिए लोगों ने इसका नाम कम ही सुना है। यह लकड़ी भारत में नहीं पाई जाती है। चंदन की लकड़ी की कीमत औसतन जहां सात से आठ हजार रुपए प्रति किलो होती है, वहीं अफ्रीकन ब्लैक वुड की कीमत करीब आठ हजार डॉलर यानी करीब साढ़े छह लाख रुपए प्रति किलो है। ऐसे में ये चंदन से कई गुणा महंगी लकड़ी है। अगर किसी शख्स के पास मात्र एक किलो अफ्रीकन ब्लैक वुड भी है तो भी वह उससे एक कार खरीद सकता है। वहीं अगर किसी के पास इसका पूरा पेड़ है तो आपका करोड़पति होना तय है।

इसलिए बढ़ी इस लकड़ी की कीमत

अफ्रीकन ब्लैक वुड रेयर ट्री है। यह दुनियाभर में मात्र 26 देशों में ही मिलता है। यह पेड़ मूल रूप से तंजानिया जैसे मध्य अफ्रीका के देशों में मिलता है। इसी के साथ सेनेगल पूर्व से इरिट्रिया तक अफ्रीका महाद्वीप के सूखे क्षेत्रों और दक्षिण अफ्रीका के मध्य और दक्षिणी भागों में ये पेड़ मिलते है। इस पेड़ की ऊंचाई 25 से 40 फीट होती है। इसके दुर्लभ होने का एक कारण यह है कि यह धरती पर सीमित संख्या में है। ऐसे में यह काफी दुर्लभ है। इस पेड़ को विकसित होने में करीब 60 साल का समय लगता है। सीमित संख्या और अधिक मांग के कारण एक ओर जहां इसकी कीमतें आसमान छू रही है, वहीं दूसरी ओर इसकी तस्करी भी बढ़ रही है।

म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से लेकर लग्जरी फर्नीचर तक उपयोग

अफ्रीकन ब्लैकवुड एक अत्यंत कठोर लकड़ी है। यह मजबूत होने के साथ ही स्थिर रहती है, ऐसे में इसपर नक्काशी करना बेस्ट रहता है। यह प्राकृतिक रूप से चिकनी और चमकदार होती है, ऐसे में इसपर पॉलिश आसानी से होती है और पॉलिश से इस लकड़ी की खूबसूरती और बढ़ जाती है। भारत में इसे संतिसाल कहा जाता है। अफ्रीकन ब्लैकवुड से लग्जरी फर्नीचर बनने के साथ ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तैयार किए जाते है। इस लकड़ी से ओबो, शहनाई जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ज्यादा बनाए जाते हैं। क्योंकि ऐसे वाद्य यंत्रों को बनाने के लिए मजबूत लकड़ी की जरूरत होती है।

कलिंग समाचार

गुरूवार 13 अगस्त 2026

मोदी-शाह की अनुपस्थिति चिंतनीय

संसद के मानसून सत्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके बाद सबसे प्रभावशाली गृह मंत्री अमित शाह की लगातार गैरमौजूदगी चिंतनीय है। जिसके कारण देश के समक्ष अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही। उनकी अनुपस्थिति के चलते लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों ही सदनों में गतिरोध है। यह भी एक विडंबना है कि जहां एक तरफ़ संसद में अहम मसलों पर चर्चा नहीं हो रही है, वहीं तकरीबन हर रोज दोनों सदनों में हो रहे शोर-शराबे का लाभ उठाकर सरकार चालाकी से शासकीय विधेयक पारित कर रही है। यह संसदीय परंपरा के विपरीत है कि जिन मुद्दों पर प्रतिपक्ष चर्चा चाहता है, उसे सत्ता पक्ष चालाकीपूर्वक टाल रहा है और दूसरी ओर बिना बहस कराये अपनी मर्जी व आवश्यकता के विधेयकों को मंजूर कर कानून रूप दे रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी एवं उसके मित्र दलों के सहयोग से तीन बार बनी सरकारों का यही रवैया रहा है लेकिन आज भारत के सामने जो बेहद महत्वपूर्ण सवाल हैं, उन्हें टालना किसी भी सूरत में लोकतंत्र के हित में नहीं है। यह सीधे-सीधे सरकार का जवाबदेही से मुकरना है। 20 जुलाई से 13 अगस्त तक के लिये तय इस सत्र के दौरान उ मीद थी कि सरकार जंतर-मंतर पर हुए युवाओं एवं छात्रों के प्रदर्शन और उसके पुलिसिया दमन पर सरकार जवाब देगी। यह प्रदर्शन मई में नीट परीक्षा के रद्द हो जाने के खिलाफ हुआ था। परीक्षा रद्द होने के चलते देश भर में 20 से अधिक छात्र-छात्राओं ने आत्महत्या कर ली। करीब डेढ़ माह चले धरना-प्रदर्शन में शामिल लोग 20 जुलाई को संसद की ओर मार्च करना चाहते थे। उन्हें रोकने के लिये प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बड़े पैमाने पर बल प्रयोग किया था। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रदर्शन तो बंद हो गया पर प्रदर्शन स्थल पर युवाओं व छात्र-छात्राओं के साथ हुई पुलिस बर्बरता से लोगों में रोष है। केन्द्र सरकार के वादे के विपरीत बड़ी सं या में प्रदर्शनकारियों को गिर तार किया गया है। कील लगी लाठियां और सादे कपड़ों में पुलिस के साथ ऐसे लोगों ने छात्रों-युवाओं पर कहर बरपाया था जिनके बारे में आरोप है कि वे भाजपा तथा उसके समर्थित संगठनों के कार्यकर्ता थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पैलेट गन से घायल युवक को मीडिया के सामने पेश किया तथा प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे युवाओं से भी तस्दीक कराई कि प्रदर्शनकारियों के साथ बर्बरता हुई। संसद के बाहर और भीतर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं कि प्रदर्शन में शामिल युवाओं का दमन करने का आदेश किसने दिया? उनके अनुसार गृह मंत्री होने के नाते अमित शाह इसके लिये जि मेदार हैं और अगर वे कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है कि यह किसके आदेश पर हुआ तो उसका अर्थ है कि वे अयोग्य हैं। दोनों ही मामलों में शाह की जवाबदेही है और उन्हें सदन में आकर जवाब देना चाहिये। पूरा विपक्ष चाहता है कि इस ग भीर मामले में गृह मंत्री के साथ प्रधानमंत्री को भी संसद में चर्चा कराकर जनता को संतुष्ट करना चाहिये। उन्हें सदनों में आकर उत्तर देने के लिये रोज ही संसद परिसर में विपक्ष द्वारा प्रदर्शन और नारेबाजी की जा रही है। बुधवार को तो समूचे विपक्ष ने मकर द्वार से गांधी प्रतिमा तक मार्च भी निकाला, ताकि सरकार पर दबाव बने। इधर यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी है, जहां छात्रों पर पुलिस के दमन से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई करते हुए मु य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि हिंसक प्रतिक्रिया कभी समाधान नहीं हो सकती, बल्कि इससे स्थिति और बिगड़ती है। उन्होंने कहा, सबसे बड़ी ताकत लोगों की बात सुनना है। यह समझना जरूरी है कि वे क्या कह रहे हैं और किस वजह से आंदोलन कर रहे हैं। मु य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शक्तिशाली राज्य की ओर से अत्यधिक स ती बरतने से स्थिति और बिगड़ सकती है। उन्होंने कहा कि मामलों को वापस लेने का निर्णय संभवत: इसी सोच के साथ लिया गया होगा। उन्होंने कहा, %ये युवा हैं। इन्हें उचित सलाह और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। राज्य की ओर से अनावश्यक आक्रामकता स्थिति को और हिंसक बना सकती है। इससे बचना जरूरी है।

आखिर ईरान पर हमलों की वजह क्या है?

वाप्पला बालाचंद्रन

ट्रंप ने कहा कि ईरान युद्ध के लिए उनका मकसद है- ईरान की मिसाइल क्षमताओं को खत्म करना, उसकी नेवी को खत्म करना, उसके न्यूक्लियर इरादों को खत्म करना तथा आतंकवादियों को हथियार देने से रोकना और इसके साथ ही ईरान में सरकार बदलने के लिए मजबूर करना। क्या ये मकसद पूरे हो सकते हैं? ईरान के खिलाफ जारी मौजूदा अमेरिकी-इज़राइल युद्ध के बारे में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी साफ नहीं हैं।

क्या यह उस तरह का है जैसा कि अर्थशास्त्री और पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट जेफरी साक्स कहते हैं कि यह युद्ध अमेरिका की %अपनी ग्लोबल बादशाहत को जारी रखने या बनाए रखने% की कोशिश है? साक्स ईरान पर हमले को %मिडिल ईस्ट पर नियंत्रण और मिडिल ईस्ट के तेल पर कंट्रोल के लिए युद्ध% बताते हैं। क्या इससे यह पता चलता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्र प ने 28 फरवरी को मार-ए-लागो से अचानक अपनी पॉलिसी क्यों बदल दी जबकि जिनेवा में उनके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव स्टीव विटकॉफ तथा जेरेड कुशनर और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची की टीम के बीच तीन राउंड की बातचीत पहले ही हो चुकी थी? उसी समय उन्होंने ईरान के चारों ओर सबसे बड़ा अमेरिकी लड़ाकू जहाजी बेड़ा इकट्ठा करना जारी रखा?

अमरेकी-इज़राइल के संयुक्त %ऑपरेशन एपिक यूरी% को शुरू करने के लिए 28 फरवरी का दिन ही क्यों चुना गया? काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में मिडिल ईस्टर्न स्टडीज़ के सीनियर फेलो इलियट अब्रा स की एक रिपोर्ट थी कि ईरान पर हमला करने का ट्र प व नेतन्याहू का फैसला संभवत: 11 फरवरी को इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के वाशिंगटन दौरे के दौरान लिया गया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दो दिन पहले के इज़रायल दौरे से इस हमले की कड़ी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भारत में इज़रायली राजदूत रियूवेन अजार के अनुसार, मोदी के 25-26 फरवरी को इज़रायल यात्रा के बाद हुए ऑपरेशन का उनके दौरे से कोई लेना-देना नहीं था। उन्होंने इसे एक %ऑपरेशनल मौका% बताया जो मोदी के इज़रायल छोड़ने और 28 फरवरी की सुबह इज़रायल की सिक्योरिटी कैबिनेट से फाइनल मंजूरी मिलने के बाद मिला।,द्यह्यश ऋडुस्त्र - राजस्थान की अनोखी तालाब संस्कृति यह %ऑपरेशनल मौका% उस बातचीत और मीडिएशन के बिल्कुल उलट है जो चर्चा चल रही थी। न्यूयॉर्क के थिंक टैंक सीएफआर ने 26 फरवरी को अपने डेली न्यूज़ ब्रीफ में ओमान के मीडिएटर के हवाले से कहा था कि विटकॉफ-अराघची बातचीत के दौरान ईरान और अमेरिका दोनों ही %नए और क्रिएटिव आइडिया और सॉल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा खुलापन% दिखा रहे थे और ट्र प व अराघची दोनों ने कहा कि %एक बेहतर डील है%। क्या यह बात ओमान ने लीक की थी जो उस युद्ध को रोकने के लिए थी जिसे वह नहीं चाहता था?

ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ज़्यादातर अमेरिकी सहयोगी- सऊदी अरब, कुवैत, कतर, अमीरात और बहरीन जो अब ईरान के निशाने पर हैं, ने ईरान से होने वाले खतरों पर अपना अनुमान बदल दिया था। ज़्यादा जानें भारतीय संविधान पुस्तकें न्यूज़ शीर्षक फ़ीड राजनीति समाचार खंड लंदन के इंटरनेशनल अफ़ेयर्स थिंक टैंक चैथम हाउस ने 19 फरवरी को अपने अनुमान में कहा कि मिडिल ईस्ट की कतर, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र जैसी सरकारों ने अपना रुख बदल लिया है। ये सरकारें जो कभी अमेरिका से ईरान और %एक्सिस ऑफ़ रेजिस्टेंस% से निपटने की अपील कर रही थीं, अब बातचीत की वकालत कर रही थीं क्योंकि उनका मानना था कि %अब सबसे बड़ा खतरा विस्तारवादी और आक्रामक इज़राइल और एक संभावित रूप से ढह चुके ईरानी राज्य की अराजकता है%। उन्हें यह भी चिंता थी कि अमेरिका ने ईरान में ऐसा कोई कदम उठाया जैसा उसने इराक में उठाया था, तो यह इस्लामिक स्टेट को जन्म देगा जो इराक के टूटने के बाद %नो-मैन्स लैंड% में उभरा था। अंतिम पहेली यह है कि, जब प्रेसिडेंट ट्र प और इज़रायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ-साफ कहा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को टारगेट किया जाएगा तो वे सुरक्षित बंकर में क्यों नहीं चले गए? 28 फरवरी को ट्र प-नेतन्याहू का %ऑपरेशन एपिक यूरी% शुरू करने का संयुक्त फैसला 12 फरवरी को इज़रायली प्राइम मिनिस्टर के दौरे के बाद व्हाइट हाउस की उस घोषणा से बिल्कुल मेल नहीं खाता जिसमें कहा गया था कि %अमेरिका और इज़राइल के बीच इस बात पर कोई %पक्का% समझौता नहीं हुआ है कि ईरान के साथ आगे कैसे बढ़ना है, लेकिन राष्ट्रपति ट्र प ने %जोर दिया था कि तेहरान के साथ बातचीत जारी रहेगी ताकि यह देखा जा सके कि क्या कोई डील हो सकती है%। ट्र प ने 24 फरवरी को स्टेट ऑफ द यूनियन के अपने संबोधन में भी इस संभावना का कोई संकेत नहीं दिया था। कार्नेगी एंडोमेंट के आकलन के अनुसार ट्र प ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के अपने दृढ़ संकल्प का उल्लेख किया और कहा कि उन्होंने अपने भाषण से %क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैन्य ठिकानों के निर्माण के बारे में धमकी भरी भाषा को हटा दिया%।

इसका कारण इस्लामिक रिपब्लिक का स्ट्रक्चर है जो %एक आइडियोलॉजिकल सिस्टम है जिसमें कई स्तर वाले कुलीन और सपोर्ट का बेस है%। यह %वन-मैन शो% नहीं है। हालांकि सभी फैसले ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के नाम पर लिए गए थे लेकिन वली नज़र जैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरानी थियोक्रेसी और डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट %मल्टी-नोडल% हैं जहां अलग-अलग स्तर पर फैसले लिए जाते हैं। वे एक मुश्किल फैसले लेने की प्रक्रिया की बात करते हैं जिसमें एक्सपर्ट्स की असेंबली शामिल है जो सक्सेशन तय करती है और सुप्रीम लीडर, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और क्लेरिकल काउंसिल्स को सलाह देती है।

इस फैसले को क्यों बदला गया? इसका एकमात्र सुराग संभवत: बीबीसी की मार-ए-लागो बयान की उस व्या या में मिलता है कि ट्र प और नेतन्याहू ने %ईरानी नेतृत्व को वर्षों से घरेलू स्तर पर अपने सबसे कमजोर बिंदु के रूप में देखा क्योंकि गाजा युद्ध के बाद क्षेत्र में उसके सहयोगी मिलिशिया का सफाया हो गया था%। क्या ट्र प की सोच थी कि यह वेनेज़ुएला-मादुरो ऑपरेशन जितना आसान होगा? या यह निर्णय केवल नेतन्याहू को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया था? ट्र प ने 3 मार्च को कहा कि ईरान युद्ध के लिए उनका मकसद है- ईरान की मिसाइल क्षमताओं को खत्म करना, उसकी नेवी को खत्म करना, उसके न्यूक्लियर इरादों को खत्म करना तथा आतंकवादियों को हथियार देने से रोकना और इसके साथ ही ईरान में सरकार बदलने के लिए मजबूर करना। क्या ये मकसद पूरे हो सकते हैं? 28 फरवरी को ही अपने एक सर्वे में सीआरएफ ने पाया कि युद्ध के बाद ईरान के बहुत कमज़ोर होने के बाद भी अमेरिका और इज़राइल के लिए थियोक्रेटिक शासन को गिराना लगभग नामुमकिन है। इसका कारण इस्लामिक रिपब्लिक का स्ट्रक्चर है जो %एक आइडियोलॉजिकल सिस्टम है जिसमें कई स्तर वाले कुलीन और सपोर्ट का बेस है%। यह %वन-मैन शो% नहीं है। हालांकि सभी फैसले ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के नाम पर लिए गए थे लेकिन वली नज़र जैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरानी थियोक्रेसी और डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट %मल्टी-नोडल% हैं जहां अलग-अलग स्तर पर फैसले लिए जाते हैं। वे एक मुश्किल फैसले लेने की प्रक्रिया की बात करते हैं जिसमें एक्सपर्ट्स की असेंबली शामिल है जो सक्सेशन तय करती है और सुप्रीम लीडर, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और क्लेरिकल काउंसिल्स को सलाह देती है। शायद इसीलिए 3 जनवरी 2020 को अमेरिका द्वारा ड्रोन से कासिम सुलेमानी को मारने के बाद भी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की कुद्स फोर्स की तेज़ी कम नहीं हुई। सुलेमानी कुद्स फोर्स का सबसे करिश्माई और सबसे डरावना चेहरा था जो आईआरजीसी की एक खास यूनिट है जो अनकन्वेंशनल लड़ाई और एक्स्ट्राटेरिटोरियल ऑपरेशन पर फोकस करती है। पिछले कुछ सालों की मुश्किलों के दौरान डीसेंट्रलाइज़ेशन का सिस्टम भले ही कम हो गया हो लेकिन %यह अभी भी सरकार को एक ऐसा कैडर देता है जो सत्ता बनाए रखने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने को तैयार है%। साथ ही %हाल के विद्रोह को दबाने से यह दिखा कि विदेश में हार का मतलब घर में कमज़ोरी नहीं है%। मिडिल ईस्ट के विशेषज्ञों का कहना है कि %शायद हालिया बमबारी से धर्मतंत्र (थियोक्रेसी) बुरी तरह घायल हो सकता है लेकिन बच जाएगा और खड़ा रहेगा%। सीएफआर में मिडिल ईस्ट स्टडीज़ के सीनियर फेलो रे ताकेह का मानना है कि इस लड़ाई के बिना भी पश्चिम को बहुत बेहतर फ़ायदा हो सकता था। उनका कहना है कि अराघची ने ऐसे प्रस्ताव रखे थे जिनमें कई सालों तक यूरेनियम एनरिचमेंट को रोकने और बाद में इसे कम लेवल पर फिर से शुरू करने की बात कही गई थी। ज़्यादा जानें ताज़ा ख़बरें सूचना शीर्षक समाचार सारांश संपादकीय लेखन कार्यशाला सीएफआर की सीनियर फेलो लिंडा रॉबिन्सन को भी लगता है कि अगर स्पेशल फोर्स तैनात की गई तो बड़ी सं या में अमेरिकी हताहत होंगे। अरब देश पहले से ही इज़राइल के साथ इन संयुक्त ऑपरेशन से परेशान हैं। सीएफआर एक्सपर्ट्स की आम राय यह है कि सिर्फ हवा या समुद्र से किए जाने वाले संयुक्त हमलों से ट्र प के बड़े मकसद पूरे नहीं हो सकते। ... और आखिर में, अयातुल्ला अली खामेनेई के बारे में ट्र प ने कहा था कि वह %अमेरिकी इंटेलिजेंस से बच नहीं पाए.

जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास

अरविन्द मोहन

भारत ने युद्ध के अरब देशों में पसरने और ईरान द्वारा अमेरिकापरस्त अरब देशों के ठिकानों पर आक्रमण करने के बाद शांति और अयुद्ध के पक्ष में बयान दिया है लेकिन अभी भी काफी सारे लोगों को इंतजार ही है कि वह ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई और उनके साथियों की हत्या की निंदा करे, ईरान पर इजरायली हमले और अमेरिकी दखल की निंदा करे। उसके बगैर उसका बयान अधूरा हैइतिहास वैसे तो दुनिया में अभी भी पांच-छह युद्ध जारी हैं और उनकी गंभीरता को कम नहीं माना जा सकता। लेकिन ईरान पर इजरायल और अमेरिकी हमले के बाद लड़ाई ने जो स्वरूप लिया है वह भयावह है और विश्वयुद्ध ज्यादा दूर नहीं लगता और पुराने दो विश्वयुद्धों से अलग बात यह है कि यह यूरोप की जमीन पर होने की जगह एशिया को अखाड़ा बनाए हुए है और अमेरिका दूर बैठा सारे तमाशे कर रहा है। अभी हमारे ऊपर सीधा हमला नहीं हुआ है न हमारी सीधी भागीदारी है लेकिन अर्थव्यवस्था, राजनयन, इतिहास, संस्कृति और समाज से लेकर हर स्तर पर हमारी इस इलाके से ऐसी भागीदारी है कि हम इससे अप्रभावित नहीं रह सकते। एक तो यह हमारे पास है। दूसरे करीब एक करोड़ भारतीय इस इलाके के उन देशों में रहकर काम करते हैं जहां युद्ध अपने पूरे रौद्र रूप में शुरू हो चुका है। उनकी कमाई और रोजी-रोटी से ज्यादा उनकी जान की बन आई है और उनसे जुड़े हिन्दुस्तानी परिवारों और पूरे हिन्दुस्तान में बेचैनी महसूस की जा रही है। फिर तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित होने लगी है जिसका असर कितना और कैसा होगा इसकी कल्पना मुश्किल है। जंगी विस्फोटों और तेल तथा गैस के ठिकानों से होने वाले प्रदूषण का असर भी कहीं एक जगह भर नहीं रुकेगा। जंग वैसे भी कितने स्थायी दोस्त और उससे ज्यादा दुश्मन बना देता है। भारत ने युद्ध के अरब देशों में पसरने और ईरान द्वारा अमेरिकापरस्त अरब देशों के ठिकानों पर आक्रमण करने के बाद शांति और अयुद्ध के पक्ष में बयान दिया है लेकिन अभी भी काफी सारे लोगों को इंतजार ही है कि वह ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई और उनके साथियों की हत्या की निंदा करे, ईरान पर इजरायली हमले और अमेरिकी दखल की निंदा करे। उसके बगैर उसका बयान अधूरा है और यही गिना जाएगा कि वह इजरायल और अमेरिका की कार्रवाई के पक्ष में है। इसमें यह तथ्य और जुड़ जाएगा कि हमले से ठीक पहले हमारे प्रधानमंत्री की इजरायल यात्रा होती है और वहां की संसद को संबोधित करने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन जाते हैं। वैसे भी भाजपा और संघ इजरायल का पक्षधर रहा है। अनेक समझौतों के साथ वह गर्मजोशी भी इसी पक्ष में गई ली जाएगी जो मोदी और नेतन्याहू के बीच दिखी। इस बीच भारत ने मुश्किल ठिकानों पर फंसे हिंदुस्तानियों को स्वदेश लाने का काम जरूर शुरू कर दिया है। लेकिन जब सं या करोड़ के आसपास हो तो यह काम कैसा और कितना मुश्किल है यह भी कल्पना की जा सकती है।जंग शुरू करने के पीछे अमेरिका या इजरायल की मंशा ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना या उसके परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करना है। इस थ्योरी को आज कोई नहीं मानता, बल्कि अभी तक ईरान पर जो हमले हुए हैं उनमें स्कूल तो निशाने पर आये हैं लेकिन किसी परमाणु ठिकाने का नंबर नहीं आया है और अभी तक ईरान का जो रवैया है और ईरानी आमजन में जो प्रतिक्रिया है उससे लगता नहीं कि वह बहुत आसानी से हथियार डालेगा या अमेरिका आसानी से उसके यहां वेनेजुएला जैसा सत्ता परिवर्तन करा लेगा। लगभग पचास साल से सत्ता पर काबिज मौजूदा सैनिक और धार्मिक जमात का ईरानी गठजोड़ वैसे भी इतना मजबूत बन चुका है कि वह किसी 86 साल के बूढ़े नेता के न रहने के चलते बिखरने वाला नहीं है। अमेरिका ईरान में अपने सैनिक या सहयोगी सैनिक भेजकर वहां की लड़ाई में टिक पाएगा इसकी गुंजाइश भी नहीं लगती। वैसे भी अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन कराने का खेल खेलकर मात खा चुका है। यह लड़ाई कभी औरतों के नाम पर होती है कभी लोकतंत्र के नाम पर। अब वह सीधे जंग में उतरने के बाद ये नाम भी नहीं ले सकता और वियतनाम से लेकर दुनिया भर के अनुभव बताते हैं कि वह इतने नाराज देश की सरजमीं पर कदम भी रखने से बचेगा। वह बाहरी खेल से सत्ता परिवर्तन जरूर चाहेगा।

हमारे लिए ईरान और खामेनेई के पक्ष में भारत भी न दे पाने की वजह ईरानी शासन का अभी तक चला स्वरूप ही है। इसमें भाजपा का इजरायल और मुसलमान %प्रेम% तो कारण है ही प्रधानमंत्री की ट्र प से मैत्री भी एक कारण है। लेकिन सच कहें तो सबसे बड़ा कारण ईरान शासन का अब तक का रिकार्ड भी है जो सही मतलब में लोकतंत्र और औरतों या दूसरे पंथों के खिलाफ रहा है। लेकिन इन सबके बावजूद इसी सरकार ने उससे व्यापारिक और अन्य संबंध रखे थे, प्रधानमंत्री वहां दौरा भी कर आये थे। और चाबहार बंदरगाह वाली संधि करके फूले न समाते थे पर उससे भी बड़ी बात यह है कि खामेनेई की मौत के बाद ईरान का कसूर कम हो गया है और इजरायल तथा अमेरिका का कसूर प्रमुख बन गया है। ऐसा भी हो गया है कि आज ईरान खाड़ी के आधा दर्जन से ज्यादा अमेरिकापरस्त देशों के नागरिक ठिकानों पर सीधे हमला करने की गलती कर रहा है तब भी उसका कसूर कम लगता है। जिस बेहयाई और बर्बर ढंग से उसके शासन प्रमुख की हत्या की गई है और उसके यहां हमले हो रहे हैं उसमें हर जवाबी कार्रवाई को %उचित% बताने के पर्याप्त तर्क मौजूद हैं।

इसलिए हमारे लिए द्वारा शांति, अयुद्ध और स्थिरता के पक्ष में बयान देना सही हो सकता है लेकिन यह अपर्याप्त है। युद्ध आज जिस दौर में और भीषण स्वरूप में है और हम उसमें जिस तरह उलझे पड़े हैं वह इससे ज्यादा कुछ की मांग करता है। अक्सर युद्ध में सही गलत की चर्चा आपको एक पक्ष में खड़े होने और फिर उसके लिए युद्ध करने तक ले जाती है इससे शांति और स्थिरता कभी नहीं आती। ज़्यादा जानें विदेश समाचार सेवा समाचार बुलेटिन हिंदी भाषा पाठ्यक्रम महाभारत की कथा सब जानते हैं और अंत भी सबको पता है। युद्ध का असली जवाब अहिंसा ही है जो सत्य के प्रति शत-प्रतिशत जवाबदेह होनी चाहिए और हमारी शांति, स्थिरता और वसुधैव कुटुंबकम की चाह के साथ हमें सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस भी होना चाहिए। यह सही है कि आज के राजनयन में देशहित सर्वोपरि है लेकिन एक झूठ का खेल हमें कहां ले जाता है यह हमने आपरेशन सिंदूर पर इन्हीं ट्र प साहब के सच झूठ के मामले में देखा है। इसी अमेरिका से व्यापार समझौते के लालच में देखा है इसलिए सच के पक्ष में बोलना, सच की बुनियाद पर रिश्ते बनाना ही समझदारी है, नैतिक है, इतिहास में नाम अमर करने वाला है।

विविध समाचार

2 दिन पहले रिलीज हुई फिल्म 'सतलुज' ओटीटी से हटाई गई, पंजाब में फेक एनकाउंटर में 25 हजार हत्याओं का फिल्म में दावा

चंडीगढ़। पंजाबी अभिनेता और गायक दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' को रिलीज के दो दिन बाद ही OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 से हटा दिया गया है। यह फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित है।

इससे पहले फिल्म का नाम 'पंजाब 95' था, जिसे लंबे समय तक रिलीज की अनुमति नहीं मिली थी। बाद में संशोधित रूप में 'सतलुज' नाम से इसे OTT पर रिलीज किया गया। फिल्म हटाए जाने के बाद दिलजीत दोसांझ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें फिल्म हटाए जाने का उतना दुख नहीं है, क्योंकि यह पहले ही दर्शकों तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि एक बार कोई फिल्म इंटरनेट पर आ जाए तो उसे पूरी तरह हटाना आसान नहीं होता। साथ ही उन्होंने टिप्पणी की कि "इस फिल्म के साथ वही हुआ, जो खालड़ा जी के साथ हुआ था।" फिल्म हटाए जाने को लेकर ZEE5 ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि "मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए अगले आदेश तक 'सतलुज' प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं रहेगी।" कंपनी ने यह भी कहा कि वह कानूनी प्रक्रिया के तहत सभी उपलब्ध विकल्पों पर विचार कर रही है ताकि फिल्म को जल्द दोबारा दर्शकों के लिए उपलब्ध कराया जा सके।

हालांकि, फिल्म हटाने के पीछे किस एजेंसी या प्राधिकरण की भूमिका रही, इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। फिल्म में जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन और उनके मानवाधिकार संबंधी कार्यों को केंद्र में रखा गया है।

कहानी में 1990 के दशक के पंजाब की पृष्ठभूमि दिखाई गई है। फिल्म में तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की 31 अगस्त 1995 को हुए बम विस्फोट में हत्या की घटना और उसके बाद 6 सितंबर 1995 को जसवंत सिंह खालड़ा के कथित अपहरण को भी कथानक का हिस्सा बनाया गया है। मुख्यमंत्री की मौत के बाद जब राजनीतिक माहौल बदला, तो पुलिस को डर था कि खालड़ा उनके इस 25 हजार अवैध दाह–संस्कार के काले राज को दुनिया के सामने न ले आएं, इसलिए वे खालड़ा का अपहरण करने का कदम उठाते हैं। खालड़ा ने अमृतसर, तरनतारन और आसपास के श्मशान घाटों के रिकॉर्ड, नगर निगम के दस्तावेज और अंतिम संस्कार रजिस्टर खंगाले। उनकी जांच में सामने आया कि बड़ी संख्या में 'लावारिस' बताकर शवों का अंतिम संस्कार किया गया, जबकि कई शव कथित रूप से उन लोगों के थे जो पुलिस हिरासत के बाद लापता हो गए थे।

उन्होंने दावा किया कि पूरे पंजाब में करीब 25,000 लोगों की अवैध हत्या और गुप्त अंतिम संस्कार किए गए। केंद्र सरकार से जुड़े सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि फिल्म के कुछ हिस्सों के दुरुपयोग की आशंका जताई गई है।

सूत्रों के अनुसार, चिंता यह है कि फिल्म की कुछ सामग्री का इस्तेमाल भारत विरोधी या खालिस्तान समर्थक तत्व अपने प्रचार के लिए कर सकते हैं, विशेष रूप से राजनीतिक रूप से संवेदनशील समय में। हालांकि, इस संबंध में सरकार की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

सीटीईटी कॉलेज, सेक्टर–26 स्थित बहुउद्देशी, हॉल का एक हिस्सा ढहा कोई जनहानि नहीं

चंडीगढ़, सेक्टर–26 स्थित सीटीईटी कॉलेज के बहुउद्देशी, हॉल का एक हिस्सा आज ढह गया। इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि या चोट नहीं हुई, क्योंकि भवन को पहले ही असुरक्षित घोषित कर उपयोग के लिए बंद कर दिया गया था। चंडीगढ़ प्रशासन के इंजीनियरिंग विभाग ने भौतिक निरीक्षण के उपरांत इस भवन को पहले ही असुरक्षित घोषित कर दिया था तथा यह सुनिश्चित किया गया था कि भवन का उपयोग न किया जाए। निर्धारित प्रक्रिया के तहत विभाग द्वारा भवन का विस्तृत संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट कराने के बाद इसकी संरचनात्मक स्थिरता एवं सुरक्षा संबंधी विस्तृत तकनीकी सलाह के लिए पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (पीईसी) को मामला भेजा गया था। इस बीच, इंजीनियरिंग विभाग द्वारा असुरक्षित भवन को ध्वस्त करने की प्रक्रिया भी पहले ही प्रारंभ कर दी गई थी। घटना के तुरंत बाद स्थल को सुरक्षित करते हुए भवन के आसपास के पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई, ताकि आम जनता का प्रवेश रोका जा सके। इंजीनियरिंग विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और स्थिति पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने पुनः स्पष्ट किया है कि जन सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं।

एसआईटी की कार्यप्रणाली निष्पक्ष जांच के बजाय राजनीतिक दबाव का माध्यम बनती जा रही है : विजय सांपला

होशियारपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय सांपला ने कहा कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा उन्हें पुनः नोटिस जारी किया गया है, जबकि वे पहले भी जांच में पूर्ण सहयोग दे चुके हैं और लिखित रूप में स्पष्ट कर चुके हैं कि आगे भी हर स्तर पर सहयोग देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि बार–बार अनुरोध करने के बावजूद आज तक उन्हें वे दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए, जिनके संबंध में उनसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। बिना संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए किसी नागरिक को बार–बार तलब करना प्राकृतिक न्याय और कानून की स्थापित प्रक्रिया के विपरीत है। उन्होंने एसआईटी को सूचित कर दिया है कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण वे 06 जुलाई को उपस्थित नहीं हो सकेंगे, किंतु 07 जुलाई को स्वयं उपस्थित होकर पूरा सहयोग देंगे। विजय सांपला ने आरोप लगाया कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा मुख्यमंत्री के संबंध में दिए गए निर्णय तथा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी से संबंधित प्रस्तावित कानून को लेकर सरकार की हुई व्यापक आलोचना के बाद सरकार बुरी तरह घबराई हुई है और जनता का ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और देश के अधिकांश राज्यों में उसकी सरकारें जनसेवा कर रही हैं। पंजाब सरकार भाजपा नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई कर अपनी राजनीतिक विफलताओं को छिपाने का असफल प्रयास कर रही है। सांपला ने कहा कि पंजाब नशे, बेरोजगारी, बिगड़ती कानून–व्यवस्था, किसानों की समस्याओं और विकास जैसे गंभीर संकटों से जूझ रहा है, लेकिन राज्य सरकार जनहित के मुद्दों से ध्यान हटाकर राजनीतिक एजेंडा चला रही है। उन्होंने दोहराया कि उन्हें संविधान, न्यायपालिका और कानून के शासन पर पूरा विश्वास है। वे निष्पक्ष जांच का स्वागत करते हैं, लेकिन जांच कानून, पारदर्शिता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए। सत्य को राजनीतिक प्रतिशोध से नहीं, बल्कि तथ्यों और निष्पक्ष जांच से ही स्थापित किया जा सकता है।

हरियाणा सीएम दफ्तर और चंडीगढ़ के स्कूलों को उड़ाने की धमकी, आज ही खुले थे स्कूल, मचा हड़कंप

चंडीगढ। बुधवार सुबह चंडीगढ़ के स्कूलों और हरियाणा सीएम के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी मिली। जानकारी के मुताबिक ये धमकी इमेल के जरिए भेजी गई। जिसके बाद पुलिस अलर्ट पर आ गई। बता दें चंडीगढ़ के स्कूल आज ही गर्मी की छुट्टियों के बाद खुले है। पहले चंडीगढ़ सेक्टर–31 स्थित एयर फोर्स स्कूल को धमकी भरा ई–मेल मिला। इसके बाद सेक्टर–37बी और 37डी के गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर–38 के विवेक हाई स्कूल, सेक्टर–26 के सेक्रेड हार्ट स्कूल और स्ट्रॉबेरी फील्ड्स हाई स्कूल, सेक्टर–40 के डीपीएस तथा सेक्टर–9 के कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल को भी इसी तरह के धमकी भरे ई–मेल मिलने की सूचना मिली। मेल में कहा कि बम धमाके, आईडी ड्रोन। चंडीगढ़ के सारे स्कूलों में दोपहर 1.11 बजे, जबकि सीएम सैनी हरियाणा आफिस दोपहर 3.11 बजे का समय दिया है। धमकी भरे ई–मेल में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर को भी निशाना बनाया गया है। इसके साथ ही दावा किया गया है कि रेलवे ट्रैक भी उनके निशाने पर हैं। लोगों से रेल यात्रा नहीं करने और 15 अगस्त को अपने बच्चों को परेड में नहीं भेजने की धमकी भी दी गई है। सूचना मिलने के उपरांत पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड की टीमें तुरंत संबंधित स्कूलों में पहुंचीं और पूरे परिसर की गहन तलाशी शुरू कर दी। एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई तथा सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाए गए। खबर लिखे जाने तक किसी भी स्कूल से कोई संदिग्ध वस्तु मिलने की सूचना नहीं थी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक करीब 40 लाख महिलाओं का पंजीकरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि जारी की गई राशि जुलाई, अगस्त और सितंबर की किस्तों के रूप में दी गई है। सभा के दौरान एक महिला लाभार्थी मंच पर पहुंची और अपने मोबाइल पर आए 4,500 के बैंक संदेश को मुख्यमंत्री को दिखाया। मुख्यमंत्री ने संदेश पढ़कर इसकी पुष्टि की। महिला ने बताया कि उसकी चार बेटियां हैं और यह राशि उनकी पढ़ाई व अन्य जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और यह योजना लाखों परिवारों के लिए राहत साबित होगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पिछले दिनों कहा था कि उनकी सरकार लगातार जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है। राज्य में घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई गई है, बिना भ्रष्टाचार के 68 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं, सड़कों का विकास किया गया है और कई टोल प्लाजा बंद कर प्रतिदिन लगभग 70 लाख की बचत सुनिश्चित की गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आज पंजाब की माताओं और बहनों के लिए बहुत बड़ा दिन है। अब तक सबने पंजाब को लूटा। भगवंत मान पहले ब्ड हैं जिन्होंने पंजाब को नहीं लूटा। सारा सरकारी पैसा लोगों तक पहुंचाया। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता देने का वादा किया था। अब विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने इस योजना को लागू कर अपने चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष के बजट में 9,300 करोड़ का प्रावधान किया है।

विमुक्त घुमंतू परिवारों के शिष्ट मंडल ने अपनी समस्याओं सम्बन्धी खन्ना को सौंपा ज्ञापन

होशियारपुर। प्रमुख जन कल्याण चौरिटेबल ट्रस्ट, पालनपुर जिला बनासकांठा, गुजरात ने पूर्व सांसद अविनाश राय खन्ना से भेंट कर गढ़शंकर तहसील के ग्राम चकरोहता में पिछले लगभग 30दृ35 वर्षों से निवास कर रहे नटदृमदारी समुदाय के परिवारों को जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाने की मांग उठाई है। उन्होंने खन्ना को बताया कि नटदृमदारी समुदाय विमुक्त एवं घुमंतू जनजातियों (एन.टी–डी.एन.टी) से संबंधित है, जिसके सदस्य देश के विभिन्न राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। यह समुदाय परंपरागत रूप से जड़ी–बूटियों, देशी औषधियों तथा पूर्वजों से प्राप्त पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान के माध्यम से आजीविका अर्जित करते हैं। समुदाय के अनेक परिवार वर्षों से पंजाब में निवास कर रहे हैं, ।

संतों की शिक्षाओं से ही समाज को बेहतर दिशा मिल सकती है : सैनी

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि संतों और महान आध्यात्मिक नेताओं का जीवन समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी शिक्षाओं और आदर्शों का पालन करके ही मानवता, सेवा, भाईचारा और आध्यात्मिक मूल्यों को मजबूत किया जा सकता है। पटियाला जिले के रोडेवाल स्थित गुरुद्वारा श्री गुफासर साहिब में बाबा पूरन दास जी महाराज की 60वीं और संत बाबा बलवंत सिंह जी (सिहोड़े वाले) की 12वीं पुण्यतिथि पर आयोजित धार्मिक सभा को संबोधित करते हुए श्री सैनी ने दोनों संतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि दोनों संतों ने अपना जीवन धर्म, तपस्या, जनकल्याण और मानवता की सेवा को समर्पित किया। जल संकट वाले क्षेत्रों में कुओं का निर्माण, शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना और गुरुद्वारों के निर्माण जैसे कार्य उनके समाज सुधारक स्वरूप को दर्शाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत बाबा बलवंत सिंह जी ने मानव सेवा, आध्यात्मिक जागृति और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया तथा युवाओं को नैतिक और धार्मिक मूल्यों से जोड़ने का कार्य किया।

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

ओडिशा समाचार

कलिंग समाचार

राउरकेला, गुरूवार 13 अगस्त 2026

ओडिशा पुलिस ने साइबर क्राइम गैंग के पांच आरोपी पकड़े, ३.५ करोड़ का फर्जीवाडा उजागर

राउरकेला १२/०८ (संवाददाता): राउरकेला पुलिस ने उदित नगर थाने में दर्ज शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ओडिशा और झारखंड से एक अंतर-राज्यीय ठगी गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ़्तार किया है। यह गिरोह पीएम किसान योजना जैसी सरकारी योजनाओं के नाम पर फर्जी एपीके फाइलों के जरिए लोगों के मोबाइल और बैंकिंग विवरण चुराता था। पुलिस जांच में अब तक 3.5 करोड़ रुपये से अधिक के संदिग्ध लेनदेन का खुलासा हुआ है और आरोपियों के बैंक खातों में जमा 47 लाख रुपये फ्रीज कर दिए गए हैं।

ओडिशा पुलिस ने अंतर-राज्यीय साइबर अपराध गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पांच लोगों को गिरफ़्तार किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, उदित नगर थाने में छह अगस्त को दर्ज शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सबसे पहले राउरकेला निवासी ज्योतिष प्रसाद वर्मा (29) उर्फ तिलक महतो को गिरफ़्तार किया।

वह पहले मोमो बेचने का काम करता था। पुलिस ने बताया कि वर्मा लोगों को ठगने के बाद धोखाधड़ी से हासिल रकम को कथित तौर पर दूसरे खातों में स्थानांतरित करता था। वर्मा से पूछताछ के बाद पुलिस ने गिरोह के चार अन्य सदस्यों को झारखंड के देवघर से गिरफ़्तार किया।

इनकी पहचान विकास कुमार मांझी (29), प्रदीप कुमार (24), सूरज कुमार (24) और मनीष कुमार यादव (25) के रूप में हुई है। राउरकेला के पुलिस अधीक्षक (एसपी) नितेश वाधवानी ने बताया कि गिरोह कथित तौर पर पीएम किसान योजना जैसी सरकारी योजनाओं के ऐप के रूप में दिखने वाली संदिग्ध 'एपीके' फाइलों का इस्तेमाल करता था। इनके जरिए आरोपी लोगों का भरोसा जीतकर उनके मोबाइल फोन और वित्तीय जानकारी तक पहुंच हासिल करते थे।उन्होंने बताया कि आरोपी इस जानकारी का इस्तेमाल यूपीआई खातों, एटीएमसे पैसे निकालने संबंधी जानकारी और मर्चेंट क्यूआर कोड तक पहुंच बनाने के लिए करते थे। इसके बाद पीड़ितों के खातों से रकम स्थानांतरित कर ली जाती थी। पुलिस ने अब तक गिरोह से जुड़े 3.5 करोड़ रुपये से अधिक के लेन-देन का पता लगाया है।

एसपी ने बताया कि जांच आगे बढ़ने के साथ यह रकम और बढ़ सकती है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ देशभर में कुल 31 शिकायतें और प्राथमिकी दर्ज हैं, जबकि उनके बैंक खातों में जमा 47 लाख रुपये की रकम 'फ्रीज' कर दी गई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 24,900 रुपये नकद, पांच मोबाइल फोन, पांच एटीएम कार्ड और एक एसयूवी (स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन) भी बरामद की है।

वाधवानी ने कहा, "गिरोह के बाकी सदस्यों की पहचान, उनकी भूमिकाओं और पैसों के लेन-देन का पता लगाने, असली लाभार्थियों की पहचान करने तथा अपराध से हासिल बाकी रकम बरामद करने के लिए जांच जारी है।

पुलिस की किसानों से गांजा छोड़ने की अपील

ब्रहमपुर १२/०८ (संवाददाता):ओडिशा पुलिस ने गजपति जिले के अदावा और आर उदयगिरि इलाकों में गांजे की तस्करी के खिलाफ सख़्त कार्रवाई करने के बाद एक जागरूकता अभियान शुरू किया है।

इस अभियान के ज़रिए लोगों, खासकर आदिवासी समुदायों से अपील की जा रही है कि वे गांजे की खेती न करें और इसके बजाय कमाई देने वाली दूसरी फसलों (कैश क्रॉप्स) को अपनाएं। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि पुलिस ने इलाके में गांजे की खेती रोकने और गजपति को गांजा-मुक्त बनाने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों से भी मदद मांगी है। आर उदयगिरि के सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर (स्ष्ठक्कह्र) राकेश कुमार साहू ने कहा, इस इलाके के दूर-दराज के इलाकों में आम तौर पर अगस्त और सितंबर में गांजे की खेती शुरू होती है। इस गैर-कानूनी काम को रोकने के लिए हमने एक जागरूकता अभियान शुरू किया है, जिसमें लोगों से अपील की जा रही है कि वे ऐसी खेती में शामिल न हों। साहू ने कहा, हमारे इस मिले-जुले मिशन का मकसद यह पक्का करना है कि इस इलाके में गांजे की खेती बिल्कुल न हो। उन्होंने बताया कि अदावा और आर उदयगिरि पुलिस थाना क्षेत्रों के तहत अलग-अलग इलाकों में बैठकें की जा चुकी हैं और सभी पंचायतों में ऐसी बैठकें करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्थानीय सरपंचों, समिति के सदस्यों और वार्ड सदस्यों ने इन बैठकों में हिस्सा लिया और अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा, अगर किसी को अपने इलाके में गांजे की खेती, उसे रखने, उसका स्टॉक करने या उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के बारे में कोई जानकारी मिलती है, तो उन्हें तुरंत पुलिस को बताना चाहिए ताकि इस गैर-कानूनी काम पर रोक लगाई जा सके। साथ ही, पुलिस ने चेतावनी दी कि अगर कोई जान-बूझकर ऐसी जानकारी छिपाता है, तो उसे नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सज़्सटेंस एक्ट के तहत सज़ा हो सकती है।

कमाई के दूसरे ज़रिया के तौर पर, पुलिस ने लोगों को खेती या बागवानी करने की सलाह दी है। बैठकों में कृषि, बागवानी, वन और बैंकिंग विभागों के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया और काजू और मक्का जैसी कैश क्रॉप्स और सागौन के पेड़ लगाने का सुझाव दिया।

उन्होंने कहा, बैठकों में हमने लोगों को सलाह दी है कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति या स्थानीय माफिया उन्हें गांजे की खेती करने के लिए उकसाता है, तो वे उनके बहकावे में न आएं। यह जागरूकता अभियान इसलिए भी अहम है क्योंकि जिले के दूर-दराज के इलाकों में बड़े पैमाने पर गांजे की खेती की खबरें मिली हैं। अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल गजपति जिला प्रशासन ने लगभग 2,500 एकड़ में लगी गांजे की फसल को नष्ट कर दिया था। पुलिस ने पिछले छह महीनों में 22 टन से ज़्यादा गांजा भी ज़ब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 22 करोड़ रुपये है। साहू ने कहा कि इस दौरान कुल 18 ड्रग तस्करों को गिरफ़्तार किया गया।

ओडिशा में रेवेन्यू कलेक्शन 7.3 प्रतिशत बढ़ा, कैपिटल खर्च में 20.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी

भुवनेश्वर १२/०८ (संवाददाता): ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने आज लोक सेवा भवन में वित्त विभाग के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व वसूली व्यवस्था को और बेहतर बनाने तथा पूंजीगत और कार्यक्रम व्यय को और बढ़ाने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के समग्र विकास के लिए जहां एक ओर कुशल राजस्व वसूली व्यवस्था की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर पूंजीगत और कार्यक्रम व्यय को बढ़ाने की भी जरूरत है। इससे राज्य की विकास दर में तेजी आ सकती है। वित्त विभाग की ओर से राजस्व प्राप्ति और व्यय पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई। बैठक में पेश आंकड़ों के अनुसार, राज्य सरकार को विभिन्न स्रोतों से होने वाली आय में 10 प्रतिशत केंद्रीय अनुदान, 31 प्रतिशत केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, 31 प्रतिशत अपना कर राजस्व और 28 प्रतिशत अपना गैर-कर राजस्व शामिल है।चालू वित्त वर्ष में जुलाई तक विभिन्न स्रोतों से कुल राजस्व वसूली 61,593 करोड़ रुपये रही है, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की राजस्व वसूली से 7.3त्न अधिक है। इसी तरह, इस साल जुलाई तक राज्य का अपना कुल राजस्व पिछले साल जुलाई की तुलना में 11.9त्न अधिक है। जुलाई तक राज्य का अपना कुल कर राजस्व भी पिछले वर्ष की तुलना में 9.3 प्रतिशत अधिक है और गैर-कर राजस्व पिछले वर्ष जुलाई की तुलना में 14.8त्न अधिक है। राजस्व वसूली में अच्छी वृद्धि दर के साथ-साथ, पिछले वर्ष की तुलना में कार्यक्रम व्यय और पूंजीगत व्यय में भी वृद्धि हुई है। इस वित्त वर्ष में जुलाई तक कार्यक्रम व्यय पिछले वर्ष की इसी अवधि के कार्यक्रम व्यय से 19.1 प्रतिशत अधिक है। इसी तरह, पूंजीगत व्यय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जुलाई तक कुल पूंजीगत व्यय 11,300 करोड़ रुपये था, जबकि पिछले साल जुलाई में यह राशि 9,399 करोड़ रुपये थी। जुलाई तक कुल पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 20.2त्न की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 2036 तक एक समृद्ध ओडिशा बनाने के उद्देश्य से कई योजनाएं तैयार कर रही है। इसके लिए बुनियादी ढांचा क्षेत्र में भारी निवेश की आवश्यकता है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले रेवेन्यू कलेक्शन और प्रोग्राम व कैपिटल खर्च ज़्यादा हैं, फिर भी मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि इसमें और सुधार किया जाना चाहिए। इसलिए, मुख्यमंत्री ने अलग-अलग विभागों को सलाह दी कि वे रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम को और बेहतर बनाने और कैपिटल खर्च बढ़ाने के लिए तेज़ी से काम करें। वित्त विभाग की ओर से, विभाग के प्रधान सचिव संजीव कुमार मिश्रा ने जानकारी पेश की।बैठक में मुख्य सचिव अनु गर्ग, विकास आयुक्त देवरंजन कुमार (डी.के.) सिंह, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव शाश्वत मिश्रा, वित्त विभाग की विशेष सचिव यामिनी सारंगी और वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

कदमटोला गाँव में सामुदायिक केंद्र बनाने का कार्य शुरू

राउरकेला १२/०८ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) के सीएसआर विभाग ने बिसरा ब्लॉक के उड़सू ग्राम पंचायत के तहत कदमटोला गांव में एक सामुदायिक केंद्र के निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह के साथ एक और महत्वपूर्ण ढांचागत विकास पहल की, जो आसपास के गांवों के समावेशी विकास के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता का हिस्सा है। मुख्य महाप्रबंधक (नगर सेवाएँ एवं सीएसआर), श्री टी. जी. कानेकर बतौर मुख्य अतिथि स्थल पर मौजूद थे । इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी (सीएसआर), सुश्री मुनमुन मित्रा, महाप्रबंधक (सीएसआर), श्री बिभाबसु मल्लिक, उप महाप्रबंधक (सीएसआर), श्री आर एस बाड़ा, सहायक महाप्रबंधक (सीएसआर), श्री बिनायक जेना, ब्लॉक चेयरमैन, बिसरा ब्लॉक, सुश्री फुलमनी केरकेट्टा, उड़सू ग्राम पंचायत के सरपंच, आरएसपी के अधिकारी, साथ ही स्थानीय ग्रामीण और गांव के बुजुर्ग भी मौजूद थे। प्रस्तावित सामुदायिक केंद्र में दो कमरे, एक बड़ा हॉल और एक सामने का बरामदा होगा, साथ ही अंदर बिजली और अन्य संबंधित सुविधाएं भी होंगी। 11 × 10 मीटर के इस सामुदायिक केंद्र का निर्माण मेसर्स एस. आर. महंती द्वारा लगभग 14 लाख रुपये की अनुमानित परियोजना लागत से किया जाएगा।ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही मांग के आधार पर इस सुविधा को लिया गया है और इससे गांव की सामाजिक, सांस्कृतिक और विकासात्मक गतिविधियों के लिए एक आम मंच के रूप में काम करने की उम्मीद है। एक बार पूरा होने के बाद, सामुदायिक केंद्र बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सामाजिक समारोहों और कल्याणकारी गतिविधियों जैसी विभिन्न सामुदायिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा, जिससे सामुदायिक सम्बन्ध और मज़बूत होंगे और गांव में जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।

चोरी और खोए 230 मोबाइल फोन पुलिस ने किया जब्त

भुवनेश्वर १२/०८ (संवाददाता): ऑपरेशन स्माइल के तहत एक बड़ी सफलता में, अंगुल पुलिस ने 230 खोए और चोरी हुए स्मार्टफोन बरामद करके उनके असली मालिकों को लौटा दिए। यह गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन का पता लगाने के मकसद से शुरू की गई पहल का तीसरा चरण है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, हैंडओवर के लिए, अंगुल में पुलिस अधीक्षक (स्क्क) के ऑफिस में खोए और बरामद मोबाइल फोन के लिए एक खास डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगाया गया था। जिन मालिकों ने पहले अपने फोन गुम या चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उन्हें इस कार्यक्रम के दौरान उनके डिवाइस मिल गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बरामद स्मार्टफोन की कुल कीमत लगभग 40 लाख रुपये है।इससे पहले, अंगुल पुलिस ने दो अलग-अलग चरणों में लगभग 45 लाख रुपये के 226 स्मार्टफोन लौटाए थे। इस पहल से, जिला पुलिस ने न सिर्फ नागरिकों को उनकी कीमती संपत्ति वापस दिलाने में मदद की है, बल्कि कानून प्रवर्तन में जनता का भरोसा भी मजबूत किया है। अधिकारियों ने कहा कि खोए हुए डिवाइस का पता लगाने और मोबाइल से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे।

सेंट्रल रेंज पुलिस ड्डत्न, सत्यब्रत भोई ने मीडियाकर्मियों से कहा, यह तीसरी बार है जब हम मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को सौंप रहे हैं। अंगुल स्क्क ने पहले एक नंबर जारी किया था, जिसके अब अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा, हम आने वाले दिनों में इस अभियान को और तेज करेंगे। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे किसी भी खोए या चोरी हुए मामले की तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें। गौरतलब है कि इससे पहले एक और घटना में, खुर्दा पुलिस ने कम से कम 28 मोबाइल फोन बरामद किए थे जो अलग-अलग समय पर चोरी हुए थे या गुम होने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने उन्हें उनके असली मालिकों को लौटा दिया था। यह हैंडओवर पिछले साल 15 दिसंबर को खुर्दा स्क्क के ऑफिस में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ था।

आरएसपी द्वारा एचपीवी टीकाकरण पर किशोर स्वास्थ्य जागरूकता शिविर आयोजित

राउरकेला १२/०८ (संवाददाता): सेल के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी) ने सीएसआर विभाग के सहयोग से किशोर स्वास्थ्य और निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने की दिशा में अपने चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में, ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल, सेक्टर-19 और इस्पात डीएवी पब्लिक स्कूल, सेक्टर-16, राउरकेला में क्रमश: 6 और 8 अगस्त, 2026 को किशोर स्वास्थ्य जागरूकता शिविर आयोजित किए।

ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल में हुए जागरूकता कार्यक्रम में लगभग 50 छात्रों ने हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. अभिलाष साहू, बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. सिद्धार्थ कुमार मेहेर और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. ट्विंकल रानी (के के रानी) द्वारा संचालित किया गया। डॉक्टरों ने छात्रों के साथ बातचीत की और उन्हें किशोर स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं के बारे में संवेदनशील बनाया, जिसमें गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर सहित एचपीवी से संबंधित बीमारियों को रोकने में एचपीवी टीकाकरण के महत्व पर विशेष ज़ोर दिया गया।

इसी तरह के एक किशोर स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन इस्पात डीएवी पब्लिक स्कूल, सेक्टर-16 में किया गया था, जिसमें लगभग 67 छात्रों ने भाग लिया। इन सत्रों का संचालन बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. विकास चंद्र पात्रा, बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. सूमी भगत और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. संजू यादव ने किया। छात्रों को स्वस्थ जीवन शैली प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया और उन्हें शारीरिक और प्रजनन स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वच्छता, पोषण और निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर आयु-उपयुक्त जानकारी प्रदान की गई।

दोनों कार्यक्रमों का एक प्रमुख फोकस मानव पेपिलोमावायरस (एचपीवी) टीकाकरण के बारे में जागरूकता पैदा करना था, जो एचपीवी संक्रमण से बचाने और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डॉक्टरों ने छात्रों के प्रश्नों को बातचीत के ज़रिए संबोधित किया और किशोरावस्था के दौरान समय पर टीकाकरण और सूचित स्वास्थ्य विकल्पों के महत्व पर प्रकाश डाला।

विशेष रूप से, एचपीवी वैक्सीन हर शनिवार शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक इस्पात जनरल अस्पताल (आईजीएच) में मुफ्त में उपलब्ध है, जिससे पात्र लाभार्थियों को निवारक टीकाकरण सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाया जा सकता है।